● वर्ष-6
● अंक-45
रायपुर, गुरुवार
24 सितंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> स्वास्थ्य सेवाओं के साथ भारतीय...

स्मृति ईरानी भाजपा की प्रदेश प्रभारी

सिद्धार्थ शंभू सह प्रभारी

रायपुर-दिल्ली। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नए भाजपा प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी श्रीमती स्मृति ईरानी को सौंपा है। उनके साथ श्री सिद्धार्थ शंभू सह प्रभारी होंगे। बिहार हरीश द्विवेदी, डा. अरविंद भदौरिया आंध्रप्रदेश, अंडमान निकोबार जय प्रकाश (दिल्ली), अरूणाचल प्रदेश डा.देवेन्द्र कुमार, असम के लिए मंगल पांडे, चंडीगड़ श्री महेन्द्र पांडे, दादारा नगर हवेली दमन एंड दीप के लिए श्रीमती वर्षाबेन नरेन्द्र भाई दोशी को प्रभारी बनाया गया है।]

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने श्रीमती स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्मृति ईरानी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी का दीर्घकालिक राष्ट्रीय अनुभव, राष्ट्रसेवा एवं संगठन के प्रति समर्पण निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमारे संगठन और जनसेवा के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएगा।

इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री सिद्धार्थ शम्भू को भी छत्तीसगढ़ के सह-प्रभारी का दायित्व मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साय ने कहा कि आपके सक्रिय सहभागिता से संगठनात्मक कार्यों को और गति मिलेगी। विभिन्न राज्यों में नवनियुक्त प्रदेश प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

गोमती साय गुजरात व सौरभ सिंह झारखंड के सहप्रभारी बनाए गए

रायपुर। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पत्थलगांव विधानसभा से विधायक एवं रायगढ़ की पूर्व सांसद श्रीमती गोमती साय को गुजरात व छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक सौरभ सिंह को झारखंड प्रदेश भाजपा का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। दोनों की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में गोमती साय जी का सार्वजनिक जीवन में लंबा अनुभव रहा है। मुझे विश्वास है कि उनके सुदीर्घ अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण का लाभ गुजरात में संगठन को मिलेगा और वे इस नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगी। वहीं सौरभ सिंह पर विश्वास जताते हुए कहा कि आपकी संगठनात्मक क्षमता और सक्रिय कार्यशैली से झारखंड में संगठन और अधिक सशक्त होगा।

नए राष्ट्रीय संयोजक के हाथ में बसपा की कमान

ईशान के नेतृत्व में यूपी-पंजाब में अपने बूते लड़ेगी पार्टी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को पार्टी की देशभर के पदाधिकारियों की बैठक में ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाने की घोषणा की। वह आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। मायावती ने कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी और केवल दमदार उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा।

पार्टी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा को सत्ता की 'मास्टर चाबी' हासिल करने के लक्ष्य में विरोधी दलों की साजिशें बाधा बन रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रिश्ते-नातों और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सरकार बनाने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। परिवारवाद पर उन्होंने कहा कि बसपा इससे हमेशा मुक्त रही है और कांशीराम ने बहुजन समाज को ही अपना परिवार माना था। उनके मुताबिक, भाई-बहन और करीबी परिवार के सदस्य भी बिना किसी लोभ के संगठन में काम कर सकते हैं।

मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और देश-प्रदेश गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, पलायन व भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच संकीर्ण, सामंती, जातिवादी होने के साथ जेन-जी, जेन अल्फा एवं आमजन विरोधी रवैये वाली है। उन्होंने जीएसटी की नई व्यवस्था और यूपीआई से जुड़ी नई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आईआईटी मुंबई में दलित छात्र की आत्महत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने जातिवाद पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि का लाभ गरीबों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रहा है। राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद ईशान आनंद ने अपने दो मिनट के संबोधन में भरोसा दिलाया कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे।

युवाओं-महिलाओं तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर

चिंतन शिविर : पीएम मोदी ने शासन व सुधारों पर किया मंथन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' बुधवार से शुरू हुआ। पहले दिन की बैठक में सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने, प्रशासनिक सुधारों, योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी और महिलाओं व युवाओं तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, चार घंटे से अधिक चली बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों को आठ समूहों में बांटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक समूह के साथ अलग-अलग बातचीत की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से विभिन्न मुद्दों पर फीडबैक लिया और सरकार के कामकाज से जुड़े कई पहलुओं पर उन्हें दिशा-निर्देश दिए। पहले दिन की चर्चा में शासन व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं तथा युवाओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के मुद्दे प्रमुख रहे। इसके अलावा सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और आम लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के तरीकों पर भी चर्चा हुई।

मंत्रियों ने 'जन विश्वास से जन आधार', सरकार के सभी क्षेत्रों में सुधार और 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्यों को लेकर भी विचार-विमर्श किया। बैठक का उद्देश्य सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा करने के साथ भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना भी है। सूत्रों के अनुसार, चिंतन शिविर में कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, नीतियों को लागू करने में आने वाली दिक्कतों और मंत्रालयों के बीच समन्वय जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर। कवर्धा के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को लगातार दो पेराई सत्रों—2024-25 और 2025-26—के लिए 'हाइएस्ट शुगर रिकवरीड्डअदर एरिया' श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन ने नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शुगर फैक्ट्री एफिशिएंसी अवॉर्ड समारोह में कारखाने को सम्मानित किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के लिए यह विशेष गौरव का अवसर है कि राज्य में पहली बार किसी सहकारी शक्कर कारखाने को इस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर कारखाने से जुड़े गन्ना उत्पादक किसानों और कारखाना प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि किसानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण गन्ने की आपूर्ति, कारखाने की तकनीकी दक्षता और बेहतर प्रबंधन से यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा, यह सम्मान किसानों की मेहनत और सहकारिता व्यवस्था की सामूहिक शक्ति का सम्मान है।

250 मदरसों पर लगेगा ताला मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

1.51 लाख सरकारी भर्तियों का रास्ता खुला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने बुधवार को 250 सरकारी मान्यता प्राप्त निजी मदरसों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला किया। एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से ज्यादातर मदरसों में छात्रों की संख्या बेहद कम या नगण्य है और बुनियादी ढांचा भी पर्याप्त नहीं है।

अधिकारी ने बताया कि इन मदरसों को फिलहाल दिसंबर तक कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वहां पढ़ रहे कुछ छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 1.51 लाख कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

अधिकारी ने कहा, मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से ऐसे 250 निजी मदरसों को बंद करने का फैसला किया है, जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है और छात्रों की संख्या नगण्य है। इन्हें दिसंबर तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।अधिकारी ने बताया कि इन संस्थानों से संबंधित रिपोर्ट दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जरूरी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

यह फैसला राज्य सरकार की ओर से 252 अनधिकृत मदरसों को बंद करने के आदेश के कुछ दिन बाद आया है। राज्य सरकार ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

13% होल्ड पदों पर दें नियुक्ति 4 साल से इंतजार : राहुल

भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के कई छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए। इनमें ओबीसी आरक्षण के तहत रुकी नियुक्तियों का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के साथ भर्ती प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद 87-13 व्यवस्था के तहत ओबीसी आरक्षण से जुड़े 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखा गया है। पत्र के मुताबिक, इन पदों पर चयनित अभ्यर्थी वर्ष 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लंबे

डेढ़ साल में 13.1% गिरा रुपया अब पलट सकता है रुख

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा है कि रुपये के मौजूदा स्तर से सिर्फ स्थिर होने ही नहीं, बल्कि मजबूत होने की भी गुंजाइश है। उनका कहना है कि पिछले करीब डेढ़ साल में रुपये में आई 13.1 फीसदी की गिरावट अस्थायी घटना हो सकती है। गुप्ता ने बुधवार को मुंबई में 13वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह बात कही। पूनम गुप्ता ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2025 से 16 सितंबर 2026 के बीच रुपये में 13.1 फीसदी की संचयी गिरावट आई है। गुप्ता के मुताबिक, इसे रुपये का जरूरत से ज्यादा कमजोर होना यानी 'ओवरकरेक्शन' भी माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूंजी प्रवाह से जुड़े उपायों की घोषणा के समय बाजार विश्लेषक भी रुपये में मजबूती की उम्मीद कर रहे थे। भुगतान संतुलन में सुधार से रुपये को कैसे फायदा होगा? डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत का भुगतान संतुलन पिछले दो वित्त वर्षों में नकारात्मक रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा 24 सितम्बर 2026, गुरुवार को 'राज्य स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह' का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागार, रायपुर में आयोजित होगा।

समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग के मंत्री टंक राम वर्मा करेंगे। इस समारोह में अन्य अतिथि के रूप में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत तथा राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय - भोपाल के उप-कार्यक्रम सलाहकार एवं क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अशोक कुमार श्रोती सहित राज्य भर से एनएसएस स्वयंसेवकों एवं अधिकारियों की भागीदारी रहेगी।

ओमान के पास मालवाहक जहाज पर हमला, एक भारतीय मृत

भारत ने बुधवार को ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशनके कॉन्टैक्ट ग्रुप की ओर से जम्मू-कश्मीर के बारे में की गई बातों को सख्ती से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि ग्रुप को पाकिस्तान को मंच देने के बजाय उसे सलाह देना बेहतर होगा। विदेश मंत्रालयने एक बयान में कहा कि इस समूह को भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने ओआईसी की ओर से जम्मू-कश्मीर के बारे में की गई बातों को बेवजह और तथ्यों के लिहाज़ से गलत बताया। एमई ने कहा कि ओआईसी को भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश भारत का अहम और अटूट हिस्सा हैं। यह बयान तब आया जब न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर पर ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिसे उसने राजनीति से प्रेरित प्रोपेगैंडा कहा। उसे बार-बार समर्थन देने से ओआईसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो और जयशंकर की मुलाकात

न्यूयॉर्क। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (ह्वह्व) से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर में होने वाली अमेरिका यात्रा से पहले हुई है; वे फ्लोरिडा में ह्व20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, जहाँ पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक भी तय है। दोनों देश व्यापार वार्ता सहित अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डॉ. जयशंकर के आने वाले दिनों में ह्वह्व को संबोधित करने की भी उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (ह्वह्व) के सत्र में भाग लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का न्यूयॉर्क दौरा बेहद व्यस्त दौर से गुजर रहा है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने वैश्विक नेताओं के साथ बैक-टू-बैक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं शुरू कर दीं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुहिम का मुस्लिम कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों ने ही कर दिया विरोध

राष्ट्रव्यापी 'सेव इंडिया, सेव शरीयत' अभियान पर जबरदस्त घमासान

नई दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता की बहस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। दरअसल, 92 मुस्लिम कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और महिला अधिकार समर्थकों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रव्यापी 'सेव इंडिया, सेव शरीयत' अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे निजी कानूनों और व्याख्याओं का बचाव नहीं किया जा सकता जो समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न से टकराते हों। उनका आरोप है कि सेव इंडिया, सेव शरीयत अभियान पुरुष-प्रधान व्यक्तिगत कानूनों और उनकी रूढ़िवादी व्याख्याओं को बचाने की कोशिश करता है, जबकि मुस्लिम महिलाओं के समान नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत कानून में सुधार की जरूरत को पीछे धकेलता है। बयान पर नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, अमोल पालेकर, तुषार गांधी, मल्लिका साराभाई, जीनत शौकत अली, तिस्ता सीतलवाड़, राम पुनियानी सहित 92 लोगों के हस्ताक्षर बताए गए हैं।

इन लोगों की आपत्ति केवल शरीयत के नाम पर चलाए जा रहे अभियान तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा अभियान राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकता है और ऐसी राजनीतिक कथा को बल दे सकता है जिसमें मुसलमानों को संवैधानिक कानून के समानांतर किसी अलग कानूनी व्यवस्था की मांग करने वाले समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया जाए। देखा जाये तो इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा क्या है और उसके बाद संविधान की समानता कहाँ से शुरू होती है?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई नया संगठन नहीं है। इसकी औपचारिक स्थापना अप्रैल 1973 में हुई थी। बोर्ड स्वयं अपने गठन का उद्देश्य मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की रक्षा और ऐसे कानूनों या न्यायिक फैसलों का विरोध बताता है, जो उसके अनुसार

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अनुप्रयोग में हस्तक्षेप करते हैं। उसके घोषित उद्देश्यों में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की निरंतरता सुनिश्चित करना और ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कानूनों अथवा न्यायिक फैसलों से उसे बचाना शामिल है।

यानी आज का 'सेव इंडिया, सेव शरीयत' अभियान अचानक पैदा हुई सोच नहीं है। व्यक्तिगत कानून को बाहरी कानूनी हस्तक्षेप से बचाना बोर्ड की स्थापना के समय से ही उसकी केंद्रीय भूमिका का हिस्सा रहा है। बोर्ड के अपने अभिलेख बताते हैं कि 1970 और 1980 के दशक से उसके प्रस्तावों में समान नागरिक संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125-127, पारिवारिक कानून, सामाजिक सुधार और शरीयत के संरक्षण जैसे मुद्दे लगातार मौजूद रहे हैं।

शाह बानो से तीन तलाक तक

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पुराने रुख को समझना हो तो शाह बानो प्रकरण से लेकर तीन तलाक तक की पूरी यात्रा को एक साथ देखना होगा। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो मामले में स्पष्ट किया कि स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मांग सकती है और यह अधिकार केवल इद्दत की अवधि तक सीमित नहीं है। बाद में संसद ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण कानून बनाया। वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून की व्याख्या करते हुए भी कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान तथा भरण-पोषण की व्यवस्था केवल इद्दत की अवधि तक सीमित समझना उचित नहीं है।

शाह बानो विवाद में मुस्लिम रूढ़िवादी नेतृत्व की ओर से न्यायालय के हस्तक्षेप का विरोध हुआ और व्यक्तिगत कानून की रक्षा को धार्मिक अधिकार का प्रश्न बनाया गया। 1986 का कानून उसी राजनीतिक दबाव के वातावरण में आया। उस समय मुस्लिम महिलाओं के संगठनों और सुधारवादी समूहों ने भी कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी। यह इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि मुस्लिम समाज के भीतर भी व्यक्तिगत कानून के प्रश्न पर कभी एकमत नहीं रहा।

सेवा संकल्प अभियान :दूरियां घटीं, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी

मोबाइल मेडिकल यूनिटों से 4.66 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित

धमतरी। धमतरी की मोबाइल मेडिकल यूनिटों ने रचा जनसेवा का नया अध्यायस्वस्थ समाज ही सशक्त और विकसित जिले की आधारशिला है। इसी सोच के साथ धमतरी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों के और अधिक करीब ले जाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट (स्रू) स्वास्थ्य सेवाओं को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सीमाओं से आगे ले जाकर उन बस्तियों और क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं, जहां लोगों के लिए स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचना हमेशा सहज नहीं होता। धमतरी जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद से इन मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं ने जिले के विभिन्न शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच को मजबूत किया है। अब तक मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से 4 लाख 66 हजार 744 मरीजों का उपचार, 1 लाख 19 हजार 370 पैथोलॉजी जांच और 4 लाख 12 हजार 116 दवाइयों का वितरण किया जा चुका है। इस दौरान जिले में 5 हजार 839 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। शासन , प्रशासन की प्राथमिकता रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जरूरतमंद नागरिकों को समय पर और सहज रूप से मिले। मोबाइल मेडिकल यूनिट इसी उद्देश्य को धरातल पर साकार करने का प्रभावी माध्यम बनी हैं। निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचने वाली इन यूनिटों में चिकित्सा दल द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक पैथोलॉजी जांच और उपचार के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लंबी दूरी तय कर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने की आवश्यकता कम हुई है। स्वास्थ्य सुविधा को नागरिकों तक पहुंचाने की यह अवधारणा जन-केंद्रित प्रशासन की भावना को मजबूत करती है।

धमतरी जिले में कुल चार मोबाइल मेडिकल यूनिट अलग-अलग क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। स्रू-1 और स्रू-2 के माध्यम से निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। स्रू-3 कुरुद-मगरलोड क्षेत्र तथा स्रू-4 नगरी-आमदी-भखारा क्षेत्र में संचालित है। इन यूनिटों के माध्यम से अलग-अलग बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर नागरिकों को उपचार एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की यह नियमित पहुंच बीमारी की पहचान और उपचार के साथ-साथ लोगों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की आदत विकसित करने में भी सहायक बन रही है। धमतरी की मोबाइल मेडिकल यूनिटों ने रचा जनसेवा का नया अध्याय मोबाइल मेडिकल यूनिटों का उद्देश्य केवल मरीजों को दवा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना भी है।

ठेका कम्पनी के अधीन किए जाने की आशंका से एकजुट हुईं मितानीन

जिलेभर की मितानिनें पहुंचीं जिला मुख्यालय, कलेक्टर और सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन।

जशपुरनगर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से हटाकर ठेका कंपनी के जरिए काम कराए जाने की आशंका को लेकर जिले भर की मितानिनें मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचीं। सुबह से ही मितानिनों के रणजीता स्टेडियम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मितानिनें कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं और ज्ञापन सौंपा। मितानिनें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भी पहुंचीं और पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। मितानिनों ने ज्ञापन में बताया कि कुछ दिनों पहले पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा से संबंधित आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर उनका और उनके परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज लिए गए थे। मितानिनों का कहना है कि दस्तावेज लिए जाने की प्रक्रिया की उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद संबंधित संस्था के लोगों से दस्तावेज लिए जाने के उद्देश्य के बारे में जानकारी चाही तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मितानिनों का कहना है कि दस्तावेज लिए जाने के बाद उनके बीच यह चर्चा शुरू हुई कि कहीं उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर किसी ठेका कंपनी के अधीन तो नहीं किया जा रहा है। इसी आशंका के चलते जिलेभर की मितानिनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। हमारे परिवार के आधार कार्ड, राशन कार्ड लिए गए। हमने पूछा भी कि ये दस्तावेज क्यों लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से फिर से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। हमने कहा कि आयुष्मान कार्ड तो एक बार बनता है, दोबारा ऐसा दस्तावेज नहीं लिया जाना चाहिए। यह हमें सही नहीं लगा। हमें कहीं से जानकारी मिल रही है कि ठेका प्रथा में लेने के लिए डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। हम ठेका प्रथा में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए सही जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं- निरमंती बाई, मितानिन,सारूडीह मितानिनों की आशंका पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। जी एस जात्रा ने कहा कि मितानिनों को हटाने या उन्हें किसी ठेका कंपनी के अधीन किए जाने की बात पूरी तरह गलत है। सीएमएचओ ने बताया कि इसी उद्देश्य से परिवार के सदस्यों से संबंधित डाटा अलग से एकत्र किया गया है और इसके लिए गूगल के माध्यम से डाटा जुटाने की प्रक्रिया की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस डाटा एकत्रीकरण का उद्देश्य मितानिनों की कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव करना नहीं है।

मेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर बना कबाड़

जशपुर। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए शहर के नजदीक बालाछापर के गोठान में स्थापित किया गया इंसीनरेटर अब उपयोग में आने के बजाय कबाड़ में तब्दील हो चुका है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्थापित इस संयंत्र को पर्यावरण संरक्षण मंडल से संचालन की अनुमति नहीं मिल सकी। इसके चलते मशीन शुरू ही नहीं हो पाई और लंबे समय तक बंद रहने के कारण इसके उपकरण खराब हो गए। वहीं जिले के अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए स्वास्थ्य विभाग अब निजी कंपनी को हर माह लाखों रुपये का भुगतान कर रहा है।

बालाछापर में इस संयंत्र की स्थापना केवल मेडिकल वेस्ट के निपटान के उद्देश्य से नहीं की गई थी, बल्कि गोठान से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना भी इसका हिस्सा थी। योजना के अनुसार महिलाओं को मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर उन्हें काम उपलब्ध कराया जाता, जिससे महिलाएं इससे आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिलने से संयंत्र शुरू नहीं हुआ और महिलाओं को रोजगार देने की पूरी योजना भी अधूरी रह गई।

सीएमएचओ डॉ। जीएस जात्रा ने बताया कि बालाछापर में लगाए गए मेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर के संचालन के लिए पर्यावरण संरक्षण विभाग से आवश्यक स्वीकृति नहीं मिल पाई। अनुमति नहीं मिलने के कारण इसका संचालन नहीं किया जा सका। लंबे समय तक बंद रहने से संयंत्र में लगे उपकरण भी खराब हो चुके हैं। अब उन्हें सुधारकर दोबारा चालू करने में काफी खर्च आने की संभावना है। यही वजह है कि फिलहाल इसके दोबारा संचालन की संभावना कम मानी जा रही है। बालाछापर बॉयो मेडिकल वेस्ट की मशीन है। कोविड के समय यह बना था लेकिन मशीन अब कंडम है। जर्जर होने की वजह से इसको चलाना मुश्किल है। इसको चलाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा, यह संभव नहीं है। पर्यावरण विभाग से अनुमित भी लेना पड़ेगा। जबतक अपडेट नहीं होगा तबतक अनुमति नहीं मिलेगी। बालाछापर की व्यवस्था शुरू नहीं होने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए निजी कंपनी की व्यवस्था पर निर्भर होना पड़ा है। जिला चिकित्सालय के साथ जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के संग्रहण और निपटान की जिम्मेदारी वीएन टेक्नो साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कंपनी के साथ शासन स्तर पर एमओयू किया गया है। कंपनी को अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट, 2 अलग-अलग केस में कवर्धा पुलिस का एक्शन

कवर्धा। सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अभद्र एवं अश्लील कमेंट करने के मामले में कबीरधाम पुलिस ने दो अलग-अलग केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। साइबर थाना कबीरधाम ने आरोपी वरूण राजपूत और जित्तू चंद्रवंशी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पहला मामला साइबर थाना में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता राकेश साहू ने आरोप लगाया कि उनके मित्र नरेश निर्मलकर ने फेसबुक पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का फोटो पोस्ट किया गया था। इसी पोस्ट पर आरोपी वरूण राजपूत ने कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अभद्र कमेंट किए। शिकायत और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया। इसी तरह दूसरे मामले में प्रकरण में शिकायतकर्ता योगेश महाजन के अनुसार आरोपी जित्तू चंद्रवंशी ने उप मुख्यमंत्री के फोटो को फेसबुक स्टोरी पर लगाकर उसके संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां कीं। स्क्रीनशॉट सहित शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस दोनों मामलों में संबंधित फेसबुक अकाउंट, कमेंट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच कर रही है। कबीरधाम पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करने की बात कही है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। एसडीओपी अखिलेश कौशिक के दिशा-निर्देशन और साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार शंकर राठौर के नेतृत्व में दोनों मामलों में वैधानिक कार्रवाई की गई।

कांकेर के रावघाट आई छुक-छुक गाड़ी, अब यात्री ट्रेन का इंतजार, तकनीकी परीक्षण पूरा

कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर और बस्तर क्षेत्र के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब दो दशक से जिस रावघाट रेल परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, वह अब रावघाट तक पहुंच चुकी है।आपको बता दें कि साल 2008 में दल्लीराजहरा तक रेल लाइन शुरु हुई थी,जो 2026 में रावघाट तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त यानी ष्टक्रस् की टीम ने रावघाट से ताडोकी तक करीब 17 किलोमीटर लंबे नए रेलखंड का निरीक्षण किया। टीम ने रावघाट रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रैक, स्टेशन, सुरक्षा व्यवस्था और रेल परिचालन से जुड़ी तकनीकी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रायपुर रेल मंडल के ष्टक्ररूदयानंद समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ष्टक्रस् निरीक्षण को देखते हुए रावघाट स्टेशन और आसपास के इलाके में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रावघाट तक रेल पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। करीब 97 किलोमीटर लंबी इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के निर्माण के दौरान नक्सली हिंसा, हमले और आगजनी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।निर्माण कार्य के दौरान हुई अलग-अलग घटनाओं में चार नागरिकों की जान भी गई। नक्सली चुनौती के बीच रेलवे और सुरक्षा बलों के लिए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती रहा।इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा और आखिरकार रेल की पटरियां रावघाट तक पहुंच गईं। यात्री ट्रेन का इंतजारअब रावघाट तक रेल लाइन पहुंचने के बाद क्षेत्रवासियों की नजरें यात्री ट्रेन के परिचालन पर टिकी हैं। ष्टक्रस् की मंजूरी मिलने के बाद इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। यात्री रेल सेवा शुरू होने से कांकेर और बस्तर क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। ष्टक्रस् के अनुमोदन के बाद जल्द ही इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकेगा।रावघाट तक रेलवे परियोजना के पहुंचने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों को आवागमन का सुगम साधन उपलब्ध होगा- दयानंद, डीआरएम, रायपुर रेल मंडल रेल के माध्यम से क्षेत्र के नागरिक विकास की नई दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे और यह क्षेत्र के लिए नई उम्मीद का संकेत है- कुंदन कुमार,कलेक्टर वहीं अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी ने रावघाट तक रेल पहुंचने को कांकेर जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

बलौदाबाजार के दंपतियों ने लिया देहदान का संकल्प

बलौदा बाजार। बलौदा बाजार जिले में दो दंपति ने अपने मृत्योपरांत देहदान की घोषणा करते हुए सेवा ही संकल्प अभियान के तहत स्वप्रेरित होकर अपना देहदान करने की घोषणा करते हुए फार्म भरा। उनके इस जनकल्याण की भावना को देखते हुए जिले के प्रभारी एवं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कलेक्टर सभाकक्ष में शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कसडोल विकासखंड के ग्राम बम्हनीडीह से फिरतराम साहू व उनकी धर्मपत्नी पुष्पा साहू ने मृत्यु के बाद देहदान की घोषणा की। दंपति ने बताया कि उन्हें उनके गुरु से प्रेरणा मिली कि इस जीवन के बाद भी यदि हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी असहाय, रोगग्रस्त व्यक्ति के काम आ जाए और उससे किसी को नया जीवन मिल जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कोई काम नहीं है। इससे प्रेरित होकर उन्होंने यह फैसला लिया, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों की भी सहमति है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्योपरांत देहदान करना चाहिए ताकि उनका अंग किसी को नया जीवन प्रदान करें।

देसी कट्टा लहराकर लोगों को धमकाने वाला युवक गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित लालबाग मैदान के पास देसी कट्टा लहराकर लोगों को धमकाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान अजय राजपूत, निवासी बस्तर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और क्राइम टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने यह हथियार वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति से खरीदा था। अब पुलिस हथियार की सप्लाई और आरोपी के संभावित कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक, अजय राजपूत के खिलाफ पहले भी ह्रष्ठक्रस् एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है और वह करीब एक साल जेल में रह चुका है। इसके अलावा, उसके किसी गैंग से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है।

बड़ा फैसला: 40 चर्चों में गैर-ईसाइयों की एंट्री पर रोक

धमतरी। जिले में प्रार्थना और चंगाई सभाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एक नया मोड़ सामने आया है। लगातार हो रहे विरोध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए क्रिश्चियन फोरम ने जिले के करीब 40 चर्चों और प्रार्थना सभाओं में गैर-ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। दरअसल, धमतरी में पिछले कुछ समय से चंगाई और प्रार्थना सभाओं को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में 1500 से अधिक आवेदन भी पहुंचे थे। इन आवेदनों में लोगों ने प्रार्थना सभाओं में स्वेच्छा से शामिल होने की इच्छा जताई थी। प्रार्थना सभाओं को लेकर बढ़ते तनाव और विरोध के बीच प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई थी। बैठक में दोनों पक्षों के बीच स्थिति को शांत रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद अब क्रिश्चियन फोरम की ओर से चर्च और प्रार्थना सभाओं को लेकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

एसीबी अधिकारी बनकर घर में घुसे, आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) का बड़ा अधिकारी बनकर घर में घुसने और गोली मारने की धमकी देकर लाखों रुपये का सामान ले जाने के मामले में धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिविल लाइन रुद्री पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपी हितेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी ने थाना सिविल लाइन रुद्री में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ आरोपी खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा अधिकारी बताते हुए उसके घर में अनधिकृत रूप से घुस आए। आरोपियों ने प्रार्थी को गोली मारने की धमकी दी और घर में रखे लैपटॉप, वनप्लस पैड और 8 मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है। शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन रुद्री में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान मामले में धारा 335 और 309(4) बीएनएस भी जोड़ी गई।

पेशाब के बहाने पुलिस को चकमा देकर भागा स्थायी वारंटी

कोरबा। कोरबा जिले के पसान थाना इलाके से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। युवती से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार 354 का स्थायी वारंटी पुलिस को चकमा देकर हिरासत से फरार हो गया। आरोपी ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और मौका पाकर भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, फरार आरोपी का नाम खीरचंद बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। न्यायालय से उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था। पसान पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। मामले में कटघोरा एसडीओपी विजय राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी धारा 354 का पुराना स्थायी वारंटी था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और टीम ने उसे हिरासत में लिया था। एसडीओपी ने बताया कि हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी।

बड़े तेवड़ा में फिर प्रार्थना सभा और धर्मांतरण का हल्ला

भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई है। एक ग्रामीण के घर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के पर प्रार्थना सभा और धर्मांतरण की आशंका पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घर को घेर लिया। हालात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आमाबेड़ा पुलिस ने स्थिति को तो नियंत्रित कर लिया, लेकिन तनाव को देखते हुए तीन दिन बाद भी गांव में पुलिस बल तैनात है। दरअसल, बड़े तेवड़ा गांव में एक ग्रामीण के घर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद गांव में यह चर्चा फैल गई कि प्रार्थना सभा आयोजित करने के साथ धर्मांतरण का काम चल रहा है। चर्चा फैलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर संबंधित घर के सामने पहुंच गए। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आमाबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों और घर मालिक के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय से भी अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया। अंतागढ़ एसडीएम और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। वहीं, घर मालिक का कहना था कि उसके घर में किसी तरह की प्रार्थना सभा या धर्मांतरण नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी पुत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग घर पर पहुंचे थे। हालांकि, ग्रामीणों की ओर से घर में प्रार्थना सभा आयोजित होने और धर्मांतरण की आशंका जताई गई। बता दें कि कुछ महीने पहले भी बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरण के आरोप को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। उस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और जिले में कई दिनों तक तनाव का माहौल बना रहा था। इसी दौरान गांव में स्थित एक चर्च में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई थी। उस घटना के बाद से ही जिला प्रशासन और पुलिस आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। फिलहाल, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद स्थिति शांत है। एहतियात के तौर पर तीन दिन बाद भी गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घर में वास्तव में किस तरह का आयोजन किया गया था।

कभी नक्सल प्रभावित रहे गांवों के युवा अब थाम रहे वर्दी की राह

सुकमा। सुकमा जिले के जिन इलाकों में कभी बंदूक और हिंसा का साया युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ता था, अब उम्मीद की एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। पूवर्ती, सिलगेर और जगरगुंडा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवक-युवतियां अब पुलिस और सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर नई राह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुकमा पुलिस लाइन में युवक और युवतियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में युवाओं की दिनचर्या सुबह करीब 5ऱ्30 बजे शुरू होती है। सुबह के सत्र में दौड़, शारीरिक दक्षता और भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित अन्य अभ्यासों पर जोर दिया जाता है। इसके बाद युवाओं को लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान सहित आवश्यक विषयों की जानकारी दी जाती है। शिविर में जिले के दूरस्थ इलाकों के युवा भी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। पूवर्ती, सिलगेर और जगरगुंडा जैसे लंबे समय तक नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों से पहुंचे युवक-युवतियां पुलिस भर्ती के लिए पसीना बहा रहे हैं। सुकमा एसपी मयंक गुर्जर प्रशिक्षण शिविर का नियमित निरीक्षण कर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। एसपी मयंक गुर्ज ने बताया कि सुकमा के नक्सल मुक्त होने के बाद यहां के युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं। विभिन्न भर्तियों की तैयारी लगातार कर रहे हैं जैसे बस्तर फाइटर्स, पुलिस भर्ती के साथ ही सरकारी भर्ती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस ऐसे युवाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रही है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को गाइड किया जा सके और वे विभिन्न भर्तियों की अच्छी जानकारी ले सकें ताकि वे अपना अच्छा परफार्मेंस कर सकें। सुकमा एसपी मयंक गुर्जर का कहना है कि हम चाहते हैं कि युवाओं के स्किल को जितना ज्यादा पॉलिस कर सकें वो करें। युवा भी पूरे उत्साह के साथ भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

पत्थलगांव विधायक गोमती साय को गुजरात में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी

रायपुर। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर नियुक्तियां करते हुए छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को दूसरे राज्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोमती साय को गुजरात का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं, अकलतरा के पूर्व विधायक सौरभ सिंह को झारखंड का सह-प्रभारी बनाया गया है। भाजपा की ओर से जारी नियुक्तियों के अनुसार, गुजरात में तरुण चुघ को प्रभारी बनाया गया है, जबकि गोमती साय और अजय महावर को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं झारखंड में गजेंद्र पटेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। झारखंड के सह-प्रभारियों में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक सौरभ सिंह और बिहार की निवेदिता सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। गोमती साय छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियों के साथ स्थानीय निकाय से लेकर संसद और विधानसभा तक का राजनीतिक सफर तय किया है। वर्तमान में वे पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं।

छत्तीसगढ़ ट्रेवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन मंत्री से की भेंट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को देश-दुनिया के मानचित्र पर और अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ट्रेवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन (ब्ज्।) के प्रतिनिधिमंडल ने आज पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने श्री अग्रवाल को 27 सितंबर को आयोजित होने वाले विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्यों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने श्री राजेश अग्रवाल के साथ छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन स्थलों के प्रभावी प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की सहभागिता बढ़ाने से संबंधित विभिन्न सुझाव भी साझा किए गए। श्री राजेश अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर विचार-विमर्श करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और जनजातीय पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बेहतर सुविधाओं, प्रभावी प्रचार-प्रसार और निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

गरज-चमक के साथ अचानक तेज बारिश

रायपुर। रायपुर में दोपहर अचानक मौसम बदला और गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने लगी,कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को जहां के तहां ठहरने मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन मौसम खराब रहने वाला है। राजधानी रायपुर में दोपहर अचानक मौसम बदला और गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में ऑरेंज और 25 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है।

बेमेतरा जिले में सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 28.49 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़-शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बेमेतरा जिले में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 28 करोड़ 49 लाख 81 हजार रूपए स्वीकृत किये गये हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में बेमेतरा जिले के दनिया उद्वहन सिंचाई योजना के विस्तारीकरण कार्य के लिए 3 करोड़ 64 लाख 92 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 254 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। धनेली जलाशय के शीर्ष कार्य बण्डपार मुरूमीकरण तथा नहर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग तथा पक्के कार्य के लिए 4 करोड़ 92 लाख 92 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 65 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। हरदी भिभौरी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 97 लाख 65 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 344 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। छिरहा एनीकट के निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 98 करोड़ 57 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। टेगना व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 98 लाख 29 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 150 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। टेमरी उद्वहन सिंचाई योजना लाईनिंग कार्य का मरम्मत तथा शेष मुख्य नहर एवं 5 माईनरों रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 97 लाख 46 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 473 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

'राम-नामी' फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर संस्कृति मंत्री ने जताया हर्ष

■ निर्देशक श्री भारतबाला गणपति सहित पूरी टीम को दी शुभकामनाएं

रायपुर। रामनामी समुदाय की अनूठी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'राम-नामी' को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री' का प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने फिल्म के निर्देशक श्री भरतबाला गणपति सहित निर्माता एवं पूरी फिल्म टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 'राम-नामी' को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलना छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। यह सम्मान केवल एक उत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मिला पुरस्कार नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण पहचान भी है।

उन्होंने कहा कि रामनामी समुदाय की परंपरा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता का विशिष्ट उदाहरण है। अपनी अनूठी आस्था, परंपराओं और जीवन मूल्यों के माध्यम से रामनामी समाज ने प्रदेश की लोक संस्कृति को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 'राम-नामी' डॉक्यूमेंट्री ने इस विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा को प्रभावी ढंग से देश के व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया है।

श्री अग्रवाल ने फिल्म के निर्देशक श्री भरतबाला गणपति और पूरी टीम के रचनात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि किसी लोक परंपरा को संवेदनशीलता और प्रभावशाली सिनेमाई प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिल्म से जुड़े प्रत्येक कलाकार, तकनीकी विशेषज्ञ, निर्माता और सहयोगी इस सम्मान के सहभागी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। यहां की लोककलाएं, लोकगीत, लोकनृत्य, जनजातीय परंपराएं, धार्मिक आस्थाएं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं प्रदेश की विशिष्ट पहचान हैं। 'राम-नामी' को मिला राष्ट्रीय सम्मान इन समृद्ध परंपराओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

संस्कृति मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'राम-नामी' को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश के अन्य लोक कलाकारों, रचनाकारों, फिल्मकारों और सांस्कृतिक कर्मियों को भी अपनी जड़ों, परंपराओं और लोक विरासत को रचनात्मक माध्यमों से सामने लाने के लिए प्रेरित करेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 की फिल्मों के लिए घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 'राम-नामी' को हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में चुना गया है। फिल्म के निर्माता बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड और निर्देशक श्री भरतबाला गणपति हैं। संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने श्री भरतबाला गणपति एवं 'राम-नामी' फिल्म की पूरी टीम को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को देश के राष्ट्रीय पटल पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण अवसर है।

रक्तदान महादान महाकुंभ में बना वर्ल्ड रिकार्ड

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 3000 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान

रायपुर। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयुर्वेद सेवा सम्मेलन के तहत रक्तदान महादान महाकुंभ का आयोजन किया गया। आयोजन में 3 हजार से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इनमें करीब 1100 महिलाएं और 2 हजार पुरुष शामिल रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं के रक्तदान करने को आयोजन की खास उपलब्धि के तौर पर देखा गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री केदार कश्यप, मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आयुर्वेद सेवा सम्मेलन में रक्तदान के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। रक्तदान महादान महाकुंभ का आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुर्वेद सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

सम्मेलन में रक्तदान के साथ-साथ अंगदान और देहदान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस आयोजन में 31 लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है, जिसमें अनुज शर्मा भी शामिल हैं। सीआरपीएफ और कलेक्टर ने पत्नी के साथ देहदान का संकल्प लिया है। भारत में प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का विशेष महत्व रहा है। केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन कर आयुर्वेद को बढ़ावा देने का काम किया है। देशभर में आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में लगातार काम कर रही है।

कांग्रेस में सीएम पद के फिर वहीं चार चेहरों पर अजय चंद्राकर का तंज

कहा- सपना देखने में क्या बुराई है

रायपुर। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए फिर वही चार चेहरों की खबर पर वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम-लट्ठ। आखिर सपना देखने में क्या बुराई है।

अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा में कांग्रेस सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने पांच साल चलाया है, अब छत्तीसगढ़ की जनता उनको दोबारा लाएगी ही नहीं। उन्होंने एक मिसाल कायम की है, वो लोगों के जहन में है। यह सब जले हुए कारतूस हैं, ऐसे ही कितने नेता हैं।

वहीं धमतरी सहित कई क्षेत्रों में प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आवेदन मिलने के दावे पर अजय चंद्राकर ने कहा कि मिशनरियां कानून के शिकंजे से बचने के लिए नए तरीक़े ईजाद कर रही हैं। जैसे प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अब क्या प्रार्थना सभा में जाने के लिए आवेदन देना पड़ेगा? मैं चर्च, मंदिर या मजार में जाऊँगा, तो आवेदन दूँगा क्या? यह बातें ही हास्यास्पद है।

वहीं कांग्रेस में अमित जोगी की एंट्री विचाराधीन होने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि अमित जोगी को ले आयेंगे, तो वो बहुत लोगों का दुकान बंद कर देंगे। उस भय के कारण उन्हें कांग्रेस में नहीं लाना चाह रहे होंगे।

अजय चंद्राकर के कांग्रेस नेताओं को जला कारतूस बताए जाने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर का बयान उनकी अपनी व्यथा को दर्शाता है। उनकी पार्टी ने ही उनको जला हुआ कारतूस बना दिया है। वहीं भाजपा के पोस्टर पर शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर तंज कसना भाजपा की आदत बन चुकी है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उनकी ही हताशा को दर्शाता है। भाजपा के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कुछ खास नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ऐसा एक पोस्ट नजर नहीं आता, जिसमें वे अपनी सरकार की उपलब्धियों सामने रख सकें।

करमा पूजा में शामिल हुईं मंत्री राजवाड़े

प्रकृति, संस्कृति और लोकपरंपराओं के संरक्षण का दिया संदेश

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े अपने गृह ग्राम बीरपुर में आयोजित प्रकृति के पावन तिहार 'करमा पूजा' में शामिल हुईं। उन्होंने ग्रामीणजनों के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं विधि-विधानपूर्वक करम देव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख, शांति, खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रकृति, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकपरंपराओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

करमा पूजा छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और जनजीवन से गहराई से जुड़ा पारंपरिक पर्व है। यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सामुदायिक एकता और लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। करम देव की पूजा के साथ ग्रामीणजन सुख-समृद्धि, अच्छी फसल और परिवार एवं समाज की खुशहाली की कामना करते हैं। पर्व के अवसर पर पारंपरिक गीत-संगीत, नृत्य और रीति-रिवाजों से गांव का वातावरण उल्लास और उत्साह से भर उठा।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं, तीज-त्योहारों और प्रकृति से जुड़े पर्वों से है। करमा जैसे लोकपर्व हमें अपनी जड़ों और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। इन परंपराओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, आपसी भाईचारा और सामूहिकता की भावना निहित है।

उन्होंने कहा कि हमारी लोकसंस्कृति और परंपराएं केवल उत्सव का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान की अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें जीवंत बनाए रखना और नई पीढ़ी को इनकी महत्ता से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं और बच्चों से भी अपनी संस्कृति, लोककलाओं एवं पारंपरिक पर्वों से जुड़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर ग्रामीणजनों ने मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए करमा पूजा की शुभकामनाएं दीं और क्षेत्र एवं प्रदेश की निरंतर प्रगति तथा सभी परिवारों के सुख-समृद्धि की कामना की।

मंत्री दयाल दास बघेल ने झाड़ू थामकर दिया स्वच्छता का संदेश

बेमेतरा में सेवा संकल्प अभियान के तहत चला जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज बेमेतरा में जिला स्तरीय भव्य स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा मेरा योगदान थीम पर सिग्नल चौक से प्रताप चौक तक चले इस अभियान में शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर श्रमदान किया।

कार्यक्रम का सबसे प्रेरक क्षण तब आया जब प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। उनके साथ विधायक श्री दीपेश साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता दीदियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने सड़क के दोनों ओर सफाई कर स्वच्छता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया।

बेसिक स्कूल ग्राउंड स्थित गांधी भवन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बघेल ने कहा, स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं, यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ परिवेश से पर्यावरण का संरक्षण होता है, वहीं गंदगी से मानव स्वास्थ्य और जीव-जंतुओं पर विपरीत असर पड़ता है। उन्होंने नागरिकों से इस अभियान को एक दिन तक सीमित न रखकर प्रतिदिन का संकल्प बनाने का आह्वान किया।

मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर जैसे सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीब, वंचित और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आया है, और छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।

अपने संबोधन में मंत्री श्री बघेल ने साइबर अपराधों को लेकर भी चेताया। उन्होंने कहा, अनजान नंबरों से आने वाले कॉल और लिंक से दूर रहें, पैसे के लेन-देन वाले किसी भी झांसे में न आएं। सतर्कता ही सुरक्षा है।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने स्वयं सफाई में भाग लेते हुए नागरिकों से अपील की कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में डालें, नालियों में कचरा न फेंकें और अपने मोहल्ले, वार्ड को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लें।

कार्यक्रम में छ.ग. रजककार विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, नगर पालिका बेमेतरा के अध्यक्ष श्री विजय सिंहा,जनपद पंचायत अध्यक्ष सुश्री हेमा दिवाकर, जिला पंचायत सीईओ सुश्री प्रेमलता पद्माकर, एसडीएम श्रीमती दिव्या पोटाई, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री अजय साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि एवं स्वच्छता दीदियां उपस्थित रहीं।

प्रधानमंत्री मोदी की लखपति दीदी पहल से मिली नई उड़ान

■ मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में निधि बनी लखपति दीदी

रायपुर। लगन, मेहनत और सही अवसर मिल जाए तो ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर सकती हैं। पेण्ड्रा विकासखंड के ग्राम अमरपुर की श्रीमती निधि तिवारी की कहानी इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल है। पशुपालन और सब्जी बाड़ी के जरिए उन्होंने अपनी आय के नए स्रोत विकसित किए और अब उनकी वार्षिक आय करीब ढाई लाख रुपये तक पहुंच गई है।

श्रीमती निधि तिवारी जून 2023 से दीप महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं और वर्तमान में समूह की अध्यक्ष हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ने के महज तीन महीने बाद उन्होंने चक्रिय निधि (आरएफ) से प्राप्त 10 हजार रुपये की सहायता से जर्सी नस्ल की गाय खरीदी। उनकी गाय से प्रतिदिन लगभग 15 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिला।

इसके छह महीने बाद निधि को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) से 60 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने इस राशि में अपनी बचत और अन्य संसाधन जोड़कर सब्जी बाड़ी का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मौसम के अनुसार अलग-अलग सब्जियों की खेती को अपनी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बनाया। निधि तिवारी ने मार्च माह में अपने खेत में टमाटर की फसल लगाई। फसल तैयार होने के बाद उन्होंने टमाटर की बिक्री शुरू की। उन्हें लगभग 40 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर बेचकर अच्छी आमदनी हो रही है। पशुपालन के साथ सब्जी उत्पादन ने उनकी आय को विविध बनाया और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद की। निधि बताती हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ने के बाद उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, समूह का सहयोग और नई दिशा मिली।

छत्तीसगढ़ में धान की खेती के सटीक एवं तकनीकी सत्यापन के लिए हुआ एमओयू

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में धान की खेती के क्षेत्रफल का सटीक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित आकलन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता सेटेलाइट-आधारित मैपिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और भू-स्थानिक डेटा के बेहतर समन्वय से राज्य की धान उपार्जन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया है। गैर-जियो-रेफरेंस्ड क्षेत्रों की मैपिंग विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम के तहत आबंटित भू-भागों और डुबान क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि क्षेत्रों की पहचान कर उनकी जीआईएस आधारित पॉलीगॉन लेयर तैयार की जाएगी, जो वर्तमान में डिजिटल रूप से मैप नहीं हैं।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए आकलन तैयार पॉलीगॉन लेयर और भू-स्थानिक डेटा के आधार पर आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान की फसल के वास्तविक रकबे का सटीक आकलन किया जाएगा। सेटेलाइट इमेजरी से सत्यापन अन्य जियो-रेफरेंस्ड क्षेत्रों में भूमि खंडों (खसरों) के अक्षांश-देशांतर का सेटेलाइट इमेजरी से मिलान कर धान की फसल की डिजिटल उपस्थिति की पुष्टि की जाएगी। इस तकनीकी पहल से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों एफआरए एवं डुबान क्षेत्र की कृषि भूमि की डिजिटल पहचान मजबूत होगी तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए एक मजबूत आधार ढाँचा तैयार होगा।

इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम उपस्थित रहीं।

सदर बाजार से नहीं जाएगी गणेश विसर्जन झांकी!

रायपुर। राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन झांकी का मार्ग इस साल से बदलने जा रहा है ! क्योंकि सदर रोड से होकर झांकी नहीं ले जाने की मांग उठ चुकी है। और इस मार्ग पर डीजे-धुमाल बजाने पर प्रतिबंध के पोस्टर लग चुके हैं।

सदर रोड सर्राफा संघ सदर रोड में डीजे-धुमाल और तेज साउंड के विरोध में उतर आया है। संघ की ओर से ज्ञापन भी पुलिस को दिया गया। संघ ने मांग की है सिटी कोतवाली चौक से कंकाली अस्पताल तक भारी आवाज वाली सभी यंत्र बंद रखे जाए।

इस बार सदर बाजार रोड से तेज साउंड, डीजे-धूमाल के साथ झांकी नहीं जाए। झांकी नहीं जाने देने को लेकर व्यापारी और स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो चुका है। सराफा व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष हरेक मालु ने कहा की इस बार सदर रोड से झांकी ना जाए। बढ़ती जनसंख्या के साथ सदर का रास्ता बहुत सकरा है। जाम की स्थिति होती है। मकान गिरने की घटना सामने आ चुकी है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है। हरेक मालु का कहना है की इस बार झांकी सदर से ना लेजाकर सीधे बूढ़ा तालाब, मालवीर रोड से होते हुए डायवर्ट कर देना चाहिए। जहां तक पंडाल लगाकर स्वागत करने का प्रश्न उठता है, वह पंडाल यहां लगाने के बजाय उस रोड पर भी लगाया जा सकता है। हमने इस संबंध में कलेक्टर और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय थाना प्रभारी से भी अनुरोध किया है। की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। जिससे किसी को भी परेशानी न हो। व्यापारियों की ये भी मांग है की तेज साउंड डीजे और धूमाल पर पूर्णत प्रतिबंध लगे। इसको लेकर अब स्थानीय और व्यापारियों का विरोध शुरू हो गया है। तेज साउंड पर प्रतिबंध लगाने सड़क पर पोस्ट चस्पा हो चुके है।

जेन जी का बदलता मूड दलों के लिए चिंता

अजीत खरे

जेन जी का बदलता मूड राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। इस वर्ग के वोटरों का मूड सब जगह एक जैसा नहीं दिखता है। विधानसभा उपचुनाव में कुछ और था, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में कुछ और। तेजी से उभरता यह नया मतदाता समूह किस बात से प्रभावित हो रहा है, इसका सटीक जवाब भी तलाश जा रहा है। पंजाब, यूपी व उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां इनकी भूमिका खासी अहम होगी, को पक्की तौर पर अपने साथ रखने की होड़ अब शुरू होगी। इसकी वजह यह है कि पूरे देश में जेन जी की राय एक जैसी नहीं दिखती और यह राय बदलती भी रहती है। भारतीय जनता पार्टी को जहां बांकीपुर व दतिया उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो इसकी एक वजह यह सामने आई कि जेन जी ने उसके विरोधियों को समर्थन दे दिया। भाजपा दोनों सीटे हार गई। इस वर्ग का मूड किस तरह स्विंग करता है, यह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में दिखा। जेन जी के सवालों पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रही कांग्रेस की एनएसयूआई को शिकस्त खानी पड़ी। इस अभियान को जेन जी का कितना साथ मिल रहा है, इसकी कुछ झलक तो डीयू नतीजों में दिख ही जाती है। इससे निकले संदेश को समझने पढ़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों इसको लेकर सतर्क हैं लेकिन बाकी दल भी चाहे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या दूसरे छोटे बड़े दल भी इसको लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। यह इन दलों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। जो दल हाल में जीते हैं,जो हाल में हारे हैं। वह संदेश समझने की कोशिश में हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी जेन जी वोटरों का अभी सामना नहीं किया है। उत्तर प्रदेश पंजाब, उत्तराखंड में अब इसकी बड़ी परीक्षा होगी। इन दलों की चुनौती है कि जेन जी को प्रतिबद्ध वोटरों के रूप में कैसे साथ लाया जाए। इसके लिए अब इन्हीं लोगों के बीच पार्टियां अपना चुनाव अभियान चलाएंगी ताकि उनकी बात समझ सकें और समझा सके। जाहिर है कि वोटरों का रुझान एक जैसा नहीं है, स्थाई नहीं है। पर बदलता रहता है । मूड स्विंग करता रहता है। भाजपा की वैचारिक जनक संस्था आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने त्रिपुनिथुरा सरकारी संस्कृत कॉलेज के संघ पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) से नियंत्रण हासिल कर लिया है। एबीवीपी ने कॉलेज संघ चुनावों में सभी सीटें जीतकर यह उपलब्धि दर्ज की है। इस परिणाम के साथ केरल में एसएफआई के गढ़ माने जाने वाले इस कॉलेज में वर्षों से चले आ रहे एसएफआई का दबदबा खत्म हो गया है। एसएफआई कई वर्षों से कॉलेज यूनियन का संचालन कर रही थी, लेकिन इस बार एबीवीपी ने चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए सभी छह प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया। यह जीत क्षेत्र में एक और राजनीतिक बदलाव के तुरंत बाद आई है। हाल ही में भाजपा ने त्रिपुनिथुरा नगरपालिका का कार्यभार संभाला है, जिससे स्थानीय निकाय में 45 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत हुआ है। एबीवीपी ने अब कैंपस में भी इसी तरह की सफलता हासिल की है। एक ऐसे कॉलेज में जो चार दशकों से अधिक समय तक वामपंथी नियंत्रण में रहा था। एबीवीपी ने इस नतीजे को एसएफआई की छात्र-विरोधी नीतियों को नकारने जैसा बताया। संगठन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि इस कॉलेज में मिली जीत से केरल के कैंपस में मौजूद एबीवीपी की दूसरी यूनिट्स को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रतिनिधि ने एसएफआई के नेतृत्व वाली पिछली यूनियनों पर संस्कृत को बढ़ावा न देने का आरोप भी लगाया।

छात्रों के कार्यक्रम में नकारात्मक राजनीति क्यों?

सुरेश हिंदुस्तानी

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संवाद है। सरकार और विपक्ष के बीच वैचारिक विरोध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब राजनीतिक संवाद का केंद्र नीतियों और जनसमस्याओं से हटकर व्यक्तियों पर टिप्पणियों, आरोपों, कटाक्षों और उपहास तक सीमित होने लगे तो लोकतांत्रिक विमर्श की गंभीरता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वर्तमान में भारत की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दल रचनात्मक विरोध की जगह अनुचित आरोप प्रत्यारोप की परिधि में लगातार सक्रिय हैं। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के उत्थान का मार्ग बिलकुल भी तैयार नहीं कर सकती।

अभी कुछ पूर्व इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से जुड़ा मिमिक्री विवाद इसका ताजा उदाहरण है। कार्यक्रम का मूल विषय विद्यार्थियों की समस्याओं, शिक्षा, परीक्षाओं, रोजगार और छात्रावास जैसी चिंताओं से जुड़ा था। लेकिन ऐसा लगा कि कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्य से भटक कर आरोपों और व्यक्तिगत खिल्ली उडाने पर ही केंद्रित होकर रह गया। आज चिंता इस बात की है कि छात्रों के सामने समस्या नहीं समाधान की चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के सामने इस अंदाज में अपनी बात रखने का प्रयास किया कि छात्र सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं। जिन बातों का उल्लेख छात्रों के समक्ष होना चाहिए, वे मुद्दे भी कार्यक्रम में पूरी तरह गायब दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे राजनीतिक दल छात्रों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।

हालांकि कार्यक्रम में कुछ मुद्दों पर सरकार पर सवाल भी उठाए। लेकिन ऐसे सवाल छात्रों के बीच नहीं आना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन गया। विपक्ष की ओर से इसे राजनीतिक व्यंग्य और अभिव्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में देखा गया। क्या अभिव्यक्ति इस प्रकार की होना चाहिए, कदापि नहीं।

यहां प्रश्न केवल मिमिक्री का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों में गंभीर मुद्दों को केंद्र में रखने के बजाय व्यक्तिगत कटाक्ष और उपहास को अधिक स्थान मिलना चाहिए?

राजनीति में व्यंग्य कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में व्यंग्य सत्ता से सवाल पूछने का माध्यम भी रहा है। नेता, सरकारें और नीतियां आलोचना के विषय बनती रही हैं। लेकिन व्यंग्य और व्यक्तिगत अवमानना के बीच एक महीन रेखा होती है। राजनीतिक विरोध कितना तीखा हो, यह राजनीतिक परिस्थितियां तय कर सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा का प्रश्न हमेशा बना रहता है।

इंदौर की घटना में भी यही बहस सामने आई। इस पूरे प्रसंग से एक बड़ा सवाल जरूर निकलता है कि क्या विद्यार्थियों के मंच पर विद्यार्थियों के मूल प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए?

यदि किसी छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, यदि परीक्षा व्यवस्था को लेकर उसके मन में चिंता है, यदि रोजगार उसके भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है या किसी छात्रा के सामने सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या है, तो राजनीति का दायित्व है कि वह इन प्रश्नों को मजबूती से उठाए। इन सवालों के उत्तर भी उसी गंभीरता से मांगे जाने चाहिए। विपक्ष यदि सरकार की शिक्षा नीति से असहमत है तो उसे आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार यदि विपक्ष के आरोपों को गलत मानती है तो उसे आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस का रास्ता है।

दुर्भाग्य यह है कि आज आरोप लगाना आसान हो गया है और आरोप का जवाब भी एक नए आरोप से देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक नेता किसी नीति पर सवाल उठाता है तो जवाब में नीति की चर्चा करने के बजाय उसके पुराने बयान खोजे जाते हैं। किसी सरकार के निर्णय पर सवाल उठता है तो विपक्ष के पुराने कार्यकाल की कमियां गिनाई जाती हैं। किसी नेता की आलोचना होती है तो उसके जवाब में दूसरे नेता की आलोचना सामने आ जाती है।

इस प्रकार राजनीतिक संवाद एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है जिसमें यह साबित करने की कोशिश होती है कि सामने वाला अधिक गलत है। लेकिन जनता का सवाल इससे अलग है कि आप क्या करेंगे? राजनीतिक दलों की ठोस योजनाएं क्या हैं। इन सवालों का उत्तर किसी आरोप से नहीं दिया जा सकता।

राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप इसलिए भी चिंता का विषय हैं क्योंकि वे धीरे-धीरे राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। समर्थक उसी भाषा को दोहराते हैं और फिर राजनीतिक मतभेद सामाजिक कटुता में बदलने लगते हैं। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का अर्थ वैमनस्य नहीं है। आज विपक्ष की ओर से सरकार के प्रति पूरी तरह कटुता का व्यवहार किया जा रहा है। इंदौर के कार्यक्रम में भी कटुता का खेल खेला गया। क्या छात्र ऐसी कटुता को अपने उत्थान और विकास के लिए जरूरी मानते हैं। यह सवाल राजनीतिक दलों से पूछने का साहस भी छात्रों को करना चाहिए।

यहां यह भी आवश्यक है कि इस प्रश्न को केवल एक दल या एक नेता तक सीमित न किया जाए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राजनीतिक मर्यादा की कसौटी सबके लिए समान होनी चाहिए। यदि विपक्ष किसी नेता की मिमिक्री करता है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए; यदि सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत कटाक्ष करता है तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से सवाल उठना चाहिए। लोकतांत्रिक मर्यादा किसी एक दल की संपत्ति नहीं है। विपक्ष को भी लोकतान्त्रिक मर्यादा के तहत कार्यक्रम करना चाहिए। इंदौर का कार्यक्रम राजनीतिक सभा या रैली नहीं था, वह छात्रों का कार्यक्रम था, इसलिए इस कार्यक्रम में प्रथम दृष्टया राजनीतिक आरोप लगना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वे अपने विरोधी को कितनी तीखी भाषा में जवाब दे सकते हैं। चुनौती यह है कि वे जनता के सामने अपनी नीतियों और योजनाओं को कितनी स्पष्टता से रख सकते हैं।

आरोप-प्रत्यारोप से तालियां मिल सकती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो सकती है और समर्थकों का उत्साह भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए, उसे यह जानने में रुचि है कि सरकार और विपक्ष उसके लिए क्या करेंगे। विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा चाहिए, उसे यह जानना है कि परीक्षा व्यवस्था कैसे विश्वसनीय बनेगी। परिवार को सुरक्षित भविष्य चाहिए, उसे राजनीतिक कटाक्षों से अधिक ठोस नीतियों की आवश्यकता है।

इसलिए आज राजनीति को फिर से मुद्दों की ओर लौटने की जरूरत है। विरोध कीजिए, लेकिन नीतियों का विरोध कीजिए। सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन तथ्यों के साथ पूछिए। विपक्ष के आरोपों का उत्तर दीजिए, लेकिन वैकल्पिक नीति के साथ दीजिए। व्यंग्य कीजिए, लेकिन ऐसी सीमा का ध्यान रखिए जहां राजनीतिक आलोचना व्यक्तिगत अपमान में न बदल जाए। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, किंतु असहमति को संवाद में बदलना उससे भी अधिक आवश्यक है। राजनीति का उद्देश्य केवल यह सिद्ध करना नहीं होना चाहिए कि दूसरा पक्ष गलत है, राजनीति का बड़ा उद्देश्य यह बताना होना चाहिए कि जनता के लिए सही रास्ता क्या है और उस रास्ते पर चलने की योजना क्या है।

आज जनता राजनीतिक दलों से यही अपेक्षा कर रही है कि वे आरोपों की राजनीति से आगे बढ़ें और समाधान की राजनीति को केंद्र में लाएं। यदि राजनीति लगातार व्यक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती रही तो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। और जब मुद्दे पीछे छूटते हैं, तब लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जनता की वास्तविक समस्याएं भी राजनीतिक विमर्श से बाहर होने लगती हैं। इसलिए समय की मांग स्पष्ट है कि कटाक्ष कम हों, संवाद बढ़े, आरोप कम हों, तथ्य बढ़ें और व्यक्तियों से अधिक मुद्दों पर राजनीति हो। यही लोकतंत्र की गरिमा भी है और जनता के प्रति राजनीति की वास्तविक जिम्मेदारी भी।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

6- बौद्धों के दार्शनिक सम्प्रदायों का विभाग

गतांक से आगे...

आधुनिक समय में जब कि बौद्ध दर्शन के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, यह आशा की जा सकती है कि परम्परा के अनुसार बौद्ध दर्शन को इन चार सम्प्रदायों में विभाजित न करके वास्तविकता को देखा जाय ।

7- बौद्धों के तथा कथित दार्शनिक सम्प्रदाय

सर्वदर्शनसंग्रह के अनुसार बौद्धों के निम्नलिखित चार दार्शनिक सम्प्रदाय हैं- (1) वैभाषिक (2) सौत्रान्तिक (3) योगाचार (4) माध्यमिक।

इन में से पहले दोनों बाह्यार्थवादी माने जाते हैं, उनका भेद सर्वदर्शनसंग्रह के अनुसार यह है कि वैभाषिक बाह्यवस्तु का प्रत्यक्ष मानते हैं; परन्तु सौत्रान्तिक बाह्यवस्तु को अनुमेय मानते हैं। सौत्रान्तिक का सिद्धान्त जैसा कि वह सर्वदर्शनसंग्रह में दिया हुआ है, बहुत अंश तक पाश्चात्य दार्शनिक लॉक की बाह्य-वस्तु-आकार-समान-ज्ञान-वाद के समान है। अर्थात् संसार के बाह्यपदार्थ वाह्य अस्तित्व रखते हैं परन्तु हम उनका साक्षात् ब्रहण नहीं करते। जो आकार हम ग्रहण करते हैं वह आकार तो हमारे ज्ञान का ही है किन्तु ज्ञान में वह आकार बाह्य-वस्तु ने अपने आकार के समान ही उत्पन्न किया है। इस लिये अपने ज्ञान के आकार से हम उसी तरह के आकारवाली बाह्यवस्तु का अनुमान कर लेते हैं। बाह्यवस्तु को हम साक्षात् रूप से कभी ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युत सदैव उसे अनुमान द्वारा ही जानते हैं। लॉक का सिद्धान्त लगभग यही है और सर्वदर्शनसंग्रह के अनुसार सौत्रान्तिक का भी यही सिद्धान्त है। सौत्रान्तिक के सिद्धान्त को नित्यानुमेय वाह्यार्थवाद या साकार ज्ञानवाद भी कहते हैं। परन्तु यहां यह कह देना आवश्यक है कि वैभाषिक और सौत्रान्तिक दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का निरूपण, जैसा कि सर्वदर्शनसंग्रह में किया गया है, वह अनेक दृष्टियों से दोषयुक्त और भ्रमपूर्ण है। **क्रमशः ...**

भीकाजी कामा के बुलंद हौसलों से कांप उठी थी ब्रिटिश हुकूमत

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 24 सितंबर को भारत की महान शख्सियत मैडम भीकाजी कामा का जन्म हुआ था। उनको भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की जननी माना जाता है। भीकाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय ध्वज फहराया था। हालांकि भीकाजी कामा के योगदान और नाम को काफी कम लोग जानते हैं। उन्होंने अंग्रेजी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी और भारत की आजादी की नींव रखने में अहम योगदान दिया था।

बॉम्बे में 24 सितंबर 1861 को भीकाजी कामा का जन्म हुआ था। वह एक अमीर पारसी व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने अपनी शुरूआती शिक्षा बॉम्बे से पूरी की और वह स्कूली जीवन में ऐसे माहौल से प्रभावित हुईं, जहां पर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था। बेहद कम उम्र से ही भीकाजी कामा राजनीतिक मुद्दों की ओर आकर्षित हुईं। साल 1885 में उनका विवाह एक प्रसिद्ध वकील रुस्तमजी कामा से हुआ। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भीकाजी कामा की भागीदारी के कारण दोनों में मतभेद पैदा होने लगे। वैवाहिक समस्याओं और खराब सेहत के चलते वह भारत छोड़कर लंदन चली गईं।

मैडम भीकाजी कामा अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और वह भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए जानी जाती हैं। इंग्लैंड में प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात दादाभाई नौरोजी से हुई। वह भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कट्टर आलोचक थे। दादाभाई नौरोजी से मुलाकात के बाद भीकाजी कामा के जीवन की दिशा बदल गई और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काम करने लगीं। इस दौरान वह लाला हर दयाल, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ जुड़ी। इसके साथ ही उन्होंने लंदन के हाइड पार्क में कई सभाओं को संबोधित किया था।

साल 1907 में स्टटगार्ट में हुए सम्मलेन के बाद भीकाजी कामा ने एक लंबा व्याख्यान दौरा शुरू किया। इस दौरे का मुख्य मकसद प्रवासी भारतीयों के बीच, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत को तैयार करना था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई थी। इसी बीच ऐसी अफवाहें उड़ने लगीं कि उनको इंग्लैंड से निकाल दिया गया है। फिर साल 1909 में वह पेरिस चली गईं। पेरिस में भीकाजी कामा का घर भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों का केंद्र बन गया था।

फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस सहयोगी बन गए, तो फ्रांसीसी अधिकारियों ने मैडम भीकाजी कामा को ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों की वजह से तीन साल के लिए नजरबंद कर दिया। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने भारतीय, आयरिश और मिस्र के क्रांतिकारियों से संपर्क बनाए रखा।

वहीं 75 साल की उम्र में मैडम भीकाजी कामा को भारत लौटने की अनुमति मिली। इसके एक साल बाद यानी की 13 अगस्त 1936 को मैडम भीकाजी कामा का निधन हो गया।

जिनपिंग की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के कूटनीतिक मायने

कमलेश पांडे

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 23 से 25 सितंबर 2026 तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। शी जिनपिंग 23 सितंबर को वाशिंगटन पहुंचे। उनका यह दौरा 25 सितंबर को समाप्त होगा, जिसके बाद उनकी वापसी होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, टैरिफ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा वैश्विक भू-राजनीति (Geopolitics) और दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शी जिनपिंग का स्वागत करने और स्टेट डिनर देने के फैसले से साफ है कि दोनों महाशक्तियां तनाव को कम कर नए तालमेल की ओर बढ़ना चाहती हैं।

लिहाजा इस यात्रा पर पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों की नजर होगी। इस पर रूस और भारत की खास नजर बनी रहेगी, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि रूस और भारत से प्रगाढ़ हो रहे चीन के रिश्तों में कुछ खलल पैदा किया जाए। चूंकि अमेरिका ने सोवियत संघ और भारत के खिलाफ चीन को रणनीतिक मजबूती दी थी, लेकिन बाद में भी उसकी भूल साबित हुई। चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने भारत को शह दिया, लेकिन यहां भी उसका दांव उल्टा पड़ गया।

इसलिए अमेरिका अब रूस और चीन से वन टू वन, और फिर जी-3 के माध्यम से बातचीत करने को उतावला है ताकि भारत, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ईरान जैसे महत्वाकांक्षी देशों को काबू में रखा जा सके। लेकिन यदि चीन व्यवहारिक कूटनीति को छोड़कर अमेरिकी मायाजाल में फंसता है तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि भारत और रूस की समझदारी इतनी परिपक्व व मजबूत है कि उन्हें आंख दिखाने वाले उसी अंतर्राष्ट्रीय फजीहत को प्राप्त करेंगे, जैसा कि अभी अमेरिका भुगत रहा है।

इस यात्रा के प्रमुख कूटनीतिक मायने - एक, व्यापार युद्ध और टैरिफ में संतुलन: अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर अत्यधिक टैरिफ और निर्यात प्रतिबंध लगाने के बावजूद चीन ने रेयर अर्थ खनिजों और महत्वपूर्ण तकनीकों की सप्लाई रोककर कड़ा रुख अपनाया। इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य नए व्यापारिक समझौते की रूपरेखा तैयार करना और दोनों देशों के बीच जारी आर्थिक/व्यापारिक तनाव को कम करना है।

दो, रेयर अर्थ और एआई की होड़: स्मार्टफोन, रक्षा सामग्री, इलेक्ट्रिक वाहनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए आवश्यक रेयर अर्थ खनिजों की वैश्विक आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना चाहता है, जबकि चीन अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर/चिप तकनीक पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील चाहता है।

तीन, वैश्विक स्थिरता और मध्य-पूर्व संकट: दुनिया के दो बड़े नेताओं का मिलना वैश्विक बाजारों और अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संदेश देता है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव और रणनीतिक समुद्री रास्तों को सुचारू रखने जैसे मुद्दों पर दोनों देश कूटनीतिक सहयोग की गुंजाइश तलाश रहे हैं।

चार, ताइवान और क्षेत्रीय सुरक्षा: चीन हमेशा से ताइवान पर अपने संप्रभु अधिकारों का दावा करता आया है। इस बैठक में अमेरिकी हथियारों की ताइवान को बिक्री पर चर्चा हो सकती है। बीजिंग इस मंच का इस्तेमाल अमेरिका को ताइवान के मामले में हस्तक्षेप कम करने का कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए करेगा।

कूटनीतिक संदर्भ के क्षेत्र, अमेरिकी हित और चीनी हित- व्यापार में अमेरिकी सोयाबीन व कृषि उत्पादों की बिक्री व बाजार पहुंच पर डील करेगा, जबकि चीन टैरिफ दरों में कमी और आर्थिक स्थिरता पर जोर देगा।

तकनीक में अमेरिका एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहेगा, जबकि चीन अमेरिकी टेक एक्सपोर्ट बैन और प्रतिबंधों से राहत चाहेगा।

सप्लाई चेन में अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स की बिना बाधा आपूर्ति चाहेगा, जबकि चीन वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में केंद्रीय भूमिका बनाए रखना चाहेगा।

अमेरिका और चीन की डील से भारत और रूस पर क्या- क्या असर पड़ सकते हैं?

अमेरिका और चीन की यह द्विपक्षीय बातचीत और प्रबंधित प्रतिस्पर्धा की दिशा में कदम भारत और रूस के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन पुराने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी रहे हैं?

अमेरिका और चीन की डील से भारत पर असर- एक, सामरिक दबाव : भारत के लिए अमेरिका-चीन का संबंध एक दोधारी तलवार है। यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक या रणनीतिक सहमति बनती है, तो भारत को डर रहता है कि अमेरिका इंडो-पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ उतनी सख्ती नहीं दिखाएगा, जितनी भारत अपनी सुरक्षा (जैसे एलएसी विवाद) के लिए चाहता है।

दो, क्वाड का भविष्य: यदि ट्रंप-शी वार्ता से दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है, तो क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया) का जो सैन्य और रणनीतिक जोर चीन को घेरने पर था, वह थोड़ा सुस्त पड़ सकता है।

तीन, सप्लाई चेन और व्यापार: चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिरोध कम होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो विकल्प भारत (मेक इन इंडिया) के रूप में उभर रहा था, उस गति पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अमेरिका-चीन की तकनीकी प्रतिस्पर्धा बनी रहने के कारण भारत को टेक/सेमीकंडक्टर निर्माण में फायदा मिलता रहेगा।

चार, भारत को वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों में स्थिरता का लाभ मिलता है जबकि चीन के खिलाफ अमेरिका का कड़ा समर्थन कम होने और ट्रेड में दबाव का जोखिम बना रहेगा।

अमेरिका और चीन की डील से रूस पर असर-एक, चीन पर बढ़ती निर्भरता: रूस और चीन वर्तमान में असीमित साझेदारी में हैं। लेकिन यदि चीन और अमेरिका अपने आर्थिक रिश्तों को सुधार लेते हैं, तो रूस को डर रहेगा कि चीन अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में आकर रूस को मिलने वाली आर्थिक और तकनीकी मदद को सीमित कर सकता है।

दो, रूस-यूक्रेन युद्ध और कूटनीति: अमेरिका-चीन शिखर वार्ता में यदि रूस-यूक्रेन संघर्ष या वैश्विक प्रतिबंधों पर कोई गुप्त सहमति बनती है, तो मॉस्को के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के रास्ते (जैसे चीन के जरिए व्यापार) कठिन हो सकते हैं।

तीन, मॉस्को की रणनीतिक स्थिति: रूस नहीं चाहता कि अमेरिका और चीन इतने करीब आ जाएं कि दुनिया में फिर से अमेरिका-चीन की जी2 (दो महाशक्तियों का प्रभुत्व) वाली व्यवस्था स्थापित हो जाए, क्योंकि इससे रूस का वैश्विक वजन कम होता है।

चार, रूस को चीन से आर्थिक व्यापार जारी रहने की उम्मीद रहेगी। जबकि चीन द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से रूस को दी जाने वाली मदद सीमित करने का जोखिम बना रहेगा।

आज का इतिहास

1493 क्रिस्टोफ़र कोलंबस ने नई दुनिया की खोज के लिए दूसरा अभियान शुरू किया था।
1688 फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
1726 ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नगर निगम अदालतों को बनाने के लिए अधिकृत किया था।
1742 बोस्टन का फैन्यूविल हॉल जनता के लिए खोला गया था।
1789 अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का कार्यालय बनाया गया था।
1805 फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट की सैनिक कार्रवाई समाप्त हुई थी।
1829 रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच एड्रियनोपोल की शांति संधि हुई थी।
1932 डॉ. भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवडा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए विधान सभाओं में सीटें सुरक्षित करने को लेकर एक विशेष समझौता हुआ था।
1932 क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेदार देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली पहली महिला बनी थी।
1937 पिंगजिंगग्वान की लड़ाई शुरू हुई थी।
1946 कैथे पैसिफिक एयरवेज़ की स्थापना हांगकांग में हुई थी।
1948 होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की गयी थी।
1965 यमन को लेकर सऊदी अरब और मिस्र के बीच समझौता हुआ था।
1968 दक्षिण अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था।
1971 ब्रिटेन ने जासूसी के आरोप में 90 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया था।
1973 गिनी बिसाऊ ने पुर्तगाल से अपनी आजादी की घोषणा की थी।
1975 डगल हेस्टन और डौग स्कॉट माउंट एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे।
1979 घाना ने संविधान को अपनाया था।
1990 पूर्वी जर्मनी ने खुद को वारसा संधि से अलग किया था।
1996 बिल क्लिंटन ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
2003 फ्रांस राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया था।
2005 आई.ए.ई.ए. ने ईरानी परमाणु के मुद्दे को सुरक्षा परिषद को सौंपने का निर्णय लिया था।
2007 बर्मा में 20,000 से 100,000 लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।
2008 थल सेनाध्यक्ष दीपक कपूर ने कपिल देव को प्रादेशिक सेना में लेफ़्टिनेंट कर्नल की मानद पदवी प्रदान की थी।

यूपी दंगल : समाजवाद की नई राजनीतिक रंगोली या महज अवसरवाद का मुखौटा?

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति को देश के सत्ता मार्ग का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ का हर चुनावी समर राजनीतिक सिद्धांतों, सामाजिक इंजीनियरिंग और रणनीतिक पैंतरों की एक नई प्रयोगशाला बन जाता है। इस समय सूबे की सियासत 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट से पूरी तरह गर्म हो चुकी है। इस बार का विमर्श लोक-कल्याणकारी नीतियों या पारंपरिक विकास मॉडलों पर कम, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बदलते वैचारिक और प्रतीकात्मक रंगों पर ज्यादा केंद्रित है। कभी लाल टोपी और हरे झंडे के पर्याय रहे अखिलेश यादव के इस नए राजनीतिक कलेवर ने उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक नई बहस में झोंक दिया है। उनके इस नए तेवर को जहां विपक्षी दल चुनावी अवसरवाद और गिरगिट की तरह रंग बदलने की संज्ञा दे रहे हैं, वहीं सपा के रणनीतिकार इसे बहुजन और वंचित समाज को एकजुट करने की एक व्यापक हाइब्रिड सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में यह सवाल मौजूं हो जाता है कि 2027 के महासमर से पहले अखिलेश यादव का यह नया रूप किसी गहरे वैचारिक परिवर्तन का संकेत है या सत्ता तक पहुँचने का महज एक तात्कालिक और व्यावहारिक शॉर्टकट?

इस पूरे विवाद के केंद्र में सबसे पहला और चौंकाने वाला बदलाव समाजवादी पार्टी के आधिकारिक चुनाव प्रचार रथ पर देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने 2027 की चुनावी यात्राओं के लिए जो नया रथ तैयार करवाया है, उसकी मुख्य रंग-योजना में इस बार भगवा और पीत आभा को सबसे प्रमुखता से स्थान दिया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहाँ सपा का रथ पूरी तरह लाल और हरे रंग के पारंपरिक समाजवादी रंग में रंगा था, वहीं इस बार भाजपा के सबसे मजबूत वैचारिक प्रतीक यानी भगवा रंग का यह सीधा प्रवेश राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर रहा है। इस रथ के माध्यम से सपा एक बेहद चतुर और बहुस्तरीय संदेश देने की कोशिश कर रही है। एक तरफ रथ पर भगवा पृष्ठभूमि के साथ बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और चौधरी चरण सिंह जैसे महापुरुषों की तस्वीरें हैं, जो सामाजिक न्याय के समेकित एजेंडे को दर्शाती हैं। दूसरी तरफ, भगवा रंग का उपयोग कर अखिलेश यादव भाजपा के उस आख्यान को कुंद करना चाहते हैं जो सपा को बहुसंख्यक विरोधी या एक वर्ग विशेष की पार्टी के रूप में चित्रित करता रहा है। यह सॉफ्ट हिंदुत्व और सोशल जस्टिस का एक ऐसा अनूठा मिश्रण है, जिसके माध्यम से सपा सवर्णों (विशेषकर सत्तारूढ़ व्यवस्था से असंतुष्ट ब्राह्मणों और राजपूतों) तथा गैर-यादव पिछड़ों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी अब किसी एक जाति या धर्म की बपौती नहीं है बल्कि वह बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक भावनाओं का भी उतना ही सम्मान करती है।

बात केवल रथ पर चढ़े भगवा रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाजवादी कुनबे का यह वैचारिक विस्तार आगे बढ़कर नीले रंग की ओर भी खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पारंपरिक रूप से समाजवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला लाल और हरा रंग अब अपनी संपूर्ण एकाधिकारवादी पहचान खोता हुआ दिख रहा है। सपा की छात्र इकाई, समाजवादी छात्र सभा ने हाल ही में अपने आधिकारिक परिधान (ड्रेस कोड) में नीली टी-शर्ट और जींस को शामिल कर लिया है, जिसके ऊपर लाल टोपी पहनी जा रही है। इसके अतिरिक्त, अखिलेश यादव स्वयं कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों और जनसभाओं में नीले रंग का गमछा ओढ़े नजर आ

रहे हैं। राजनीति में प्रतीकों का अपना एक अनूठा और गहरा महत्व होता है। नीला रंग दशकों से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की वैचारिक विरासत का मुख्य प्रतीक रहा है। सपा के इस नीले प्रेम को सीधे तौर पर मायावती के कमजोर होते दलित जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने गैर-जाटव दलितों और अति-पिछड़ों के एक बड़े हिस्से का समर्थन हासिल कर शानदार सफलता दर्ज की थी। अब अखिलेश यादव उस क्षणिक सफलता को 2027 में एक स्थायी वोट बैंक में तब्दील करना चाहते हैं, जिसके लिए वे पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे को केवल जुबानी जमा-खर्च तक सीमित न रखकर पार्टी के दृश्य रूप (विजुअल अपीयरेंस) में भी ढाल रहे हैं।

अखिलेश यादव की इस बदलती बहुरंगी रणनीति ने विपक्ष, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का एक बड़ा हथियार दे दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सपा के इस कदम को दलितों और पिछड़ों के साथ एक नया छल करार दिया है। उनका तर्क है कि जो समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में दलित महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और जिलों के नाम बदलने में व्यस्त थी, वह आज केवल चुनाव जीतने के लिए नीले रंग का स्वांग रच रही है और उनका नया पीडीए रथ उनके अपने लाल रंग से कम और आरएसएस-भाजपा के भगवा रंग में ज्यादा रंगा नजर आ रहा है। मायावती ने इसे गिरगिट की तरह रंग बदलना और वैचारिक दिवालियापन कहा है। दूसरी ओर, भाजपा और उसके सहयोगी दल जैसे सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इसे सपा का चुनावी पाखंड बता रहे हैं। सत्तापक्ष का आरोप है कि सपा अपनी पुरानी मुस्लिम-यादव (एम-वाई) समीकरण वाली छवि से डरी हुई है और बहुसंख्यक समाज के गुस्से से बचने के लिए अब भगवा और नीले रंग की आड़ ले रही है। विरोधियों का कहना है कि सिर्फ पोशाक और रथ का रंग बदल लेने से कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सपा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और अतीत की गलतियाँ जनता के मानस पटल से गायब नहीं हो सकतीं।

हालांकि, अगर इस पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव की यह कवायद महज तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोची-सोची लॉन्ग-टर्म रणनीति का हिस्सा है। मुलायम सिंह यादव के दौर की समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय और विशिष्ट सामाजिक समीकरण पर आधारित पार्टी थी। अखिलेश यादव भली-भांति जानते हैं कि आज के उत्तर प्रदेश में केवल यादव और मुस्लिम मतों के सहारे भाजपा जैसी साधन-संपन्न और वैचारिक रूप से मजबूत चुनावी मशीनरी को मात देना असंभव है। 2017, 2019 और 2022 की लगातार हारों ने सपा को यह सिखाया है कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए उसे अपनी सर्वसमावेशी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। इसलिए, उन्होंने 75 जिले, 75 घोषणापत्र जैसी माइक्रो-लेवल प्लानिंग की शुरुआत की है, जो यह दर्शाती है कि सपा अब केंद्रीकृत राजनीति के बजाय जमीनी और स्थानीय मुद्दों को तरजीह दे रही है। 27 में 27 हजार का नारा भी इसी सूक्ष्म रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत बूथ स्तर पर भाजपा के पारंपरिक वोटों को काटने और अपने पाले में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पूरे कलर गेम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अखिलेश यादव इस प्रक्रिया में अपने कोर वोट बैंक यानी अल्पसंख्यकों को खोने का जोखिम भी उठा रहे हैं या कम से कम ऐसा विपक्ष को लगता है। जब मायावती यह सवाल उठाती हैं कि क्या सपा का मुसलमानों से भरोसा उठ गया है?, तो वे वास्तव में मुस्लिम मतदाताओं के भीतर एक असुरक्षा की भावना पैदा करने का प्रयास कर रही होती हैं। लेकिन अखिलेश यादव की इस रणनीति के पीछे एक गहरा गणित है। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मतदाता वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा को हराने में सक्षम सबसे मजबूत विकल्प के साथ ही जाएगा, और वह विकल्प फिलहाल सपा ही है। इसलिए, मुस्लिम मतों के बिखरने का खतरा कम देखते हुए अखिलेश अपनी पूरी ऊर्जा उस बहुसंख्यक और दलित आबादी को जोड़ने में लगा रहे हैं जो अब तक उनसे दूर रही थी। यह एक बड़ा राजनीतिक जुआ है, जिसमें यदि वे सफल रहे तो भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, और यदि विफल रहे तो पार्टी अपने पारंपरिक आधार से भी हाथ धो सकती है। देखा जाय तो राजनीति में रंगों का बदलना कोई नई बात नहीं है। विचारधाराएं समय के साथ अपनी प्रासंगिकता और व्यावहारिकता के अनुसार खुद को ढालती आई हैं।

स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी हो न्यायपालिका लोकतंत्र का प्रहरी

हरबंश दीक्षित

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी-विवाद के संदर्भ में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा उठाया गया प्रश्न न्यायिक जवाबदेही के विषय को फिर चर्चा के केंद्र में ले आया है। बीते 14 सितंबर, 2026 को छठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में साल्वे ने पूछा कि यदि ऐसी घटना किसी मंत्री के घर हुई होती, तो क्या कानून उसी प्रकार आगे बढ़ता, जिस प्रकार न्यायमूर्ति वर्मा के प्रकरण में हुआ। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि न्यायिक स्वतंत्रता को जवाबदेही से अलग कैसे माना जा सकता है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। हरीश साल्वे ने उन नागरिकों की चिंता को स्वर दिया है, जो न्यायपालिका को लोकतंत्र का अंतिम सांविधानिक प्रहरी मानते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को शिखर पर देखना चाहते हैं। नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा, सत्ता पर नियंत्रण और कानून के शासन के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं हो सकता। स्वतंत्रता न्यायाधीश को बाहरी दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की शक्ति देती है, जबकि जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि उस शक्ति का प्रयोग कानून, नैतिकता और संस्थागत मर्यादा के अनुसार हो। भारतीय संविधान ने इस संतुलन को स्पष्ट रूप से महत्व दिया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का आधार है और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की दिशा देता है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया के बाद हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(5) संसद को इस जांच और सिद्धि की प्रक्रिया को कानून द्वारा निर्धारित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 217 और 218 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संदर्भ में इसी सांविधानिक व्यवस्था को लागू करते हैं। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों को राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव से बचाना है। लेकिन न्यायाधीश को पद से हटाने की कठिन सांविधानिक प्रक्रिया का यह अर्थ नहीं है कि गंभीर आचरण-संबंधी शिकायतों की जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। न्यायपालिका ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए 'इन-हाउस प्रोसीजर' जैसी व्यवस्था विकसित की है। इसका एक उद्देश्य निराधार शिकायतों और अनुचित दबाव से न्यायाधीशों की रक्षा करना भी है। लेकिन आंतरिक जांच, आपराधिक जांच और न्यायाधीश को पद से हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया-तीनों अलग-अलग प्रकृति की हैं। इसलिए इनके बीच संबंध, सीमाएं और कार्रवाई की परिस्थितियां अधिक स्पष्ट होना जरूरी है। पारदर्शिता का अर्थ यह नहीं है कि हर शिकायत को सार्वजनिक कर दिया जाए। शिकायतकर्ता की गोपनीयता, न्यायाधीश की प्रतिष्ठा, जांच की निष्पक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता—सभी का ध्यान रखना जरूरी है। स्वयं प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उसी कार्यक्रम में कहा कि न्यायपालिका को निष्पक्ष, सूचनापरक और रचनात्मक आलोचना के लिए खुला रहना चाहिए। कोई भी संस्था स्वयं को जांच-पड़ताल से अलग नहीं रख सकती। उन्होंने न्यायाधीशों के विरुद्ध मौजूदा शिकायत-व्यवस्था को मजबूत और समयबद्ध बताते हुए उसमें सुधार की संभावना को भी स्वीकार किया। न्यायिक जवाबदेही का प्रश्न केवल शिकायतों तक नहीं, बल्कि न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण से भी जुड़ा है।

इस बार भी मोदी नहीं जाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा

नीरज कुमार दुबे

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र की शुरुआत के साथ ही भारत की कूटनीतिक सक्रियता तेज हो गई है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जयशंकर 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान कई देशों के नेताओं तथा विदेश मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध, ऊर्जा संकट, व्यापारिक टकराव और बदलते शक्ति संतुलन से जूझ रही है तब इस सत्र से काफी उम्मीदें की जा रही हैं।

हम आपको बता दें कि इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रतिनिधि जुट रहे हैं। इस बार का केंद्रीय विषय है, विश्वास बहाल करना, बदलाव को संभालना और ऐसा संयुक्त राष्ट्र बनाना जो सभी के लिए परिणाम दे। महासचिव अंतोनियो गुतारेस ने वैश्विक नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की अपील की है। यह उनके कार्यकाल का अंतिम महासभा सत्र भी है। ऐसे माहौल में भारत के सामने अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को बेहद स्पष्ट और मजबूती से रखने का अवसर है।

देखा जाये तो जयशंकर की यात्रा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भारत-अमेरिका संबंध इस समय कई कठिन सवालों से गुजर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा भारी

शुल्क लगाने की व्यवस्था ने नई दिल्ली की ऊर्जा सुरक्षा और वाशिंगटन के साथ व्यापारिक संबंधों के बीच तनाव पैदा किया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी कानून राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों पर सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने की शक्ति देता है। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने लगभग एक अरब चालीस करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है और वह अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखेगा।

यहीं से जयशंकर की न्यूयॉर्क यात्रा का असली सामरिक महत्व सामने आता है। भारत को एक साथ रूस के साथ अपने ऊर्जा और सामरिक संबंधों, अमेरिका के साथ व्यापार और सुरक्षा साझेदारी तथा ग्लोबल साउथ की चिंताओं को साधना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा इस संतुलन को साधने के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच उपलब्ध कराती है। जयशंकर की दर्जनों मुलाकातों में ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, विकास और ग्लोबल साउथ के मुद्दे स्वाभाविक रूप से प्रमुख रहेंगे।

इसके अलावा, भारत के लिए इस महासभा का एक अहम उद्देश्य 2028 से शुरू होने वाले दो वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल करने के समर्थन में विभिन्न देशों को साथ लाना भी है। इसके लिए जयशंकर अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों के सामने भारत का छह सूत्रीय घोषणापत्र रखेंगे और सुरक्षा परिषद में भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे। साथ ही, ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में भारत की भूमिका, आर्थिक एवं मानवीय सहायता तथा संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। पिछले वर्ष महासभा के दौरान जयशंकर ने 47 द्विपक्षीय और 10 बहुपक्षीय बैठकें की थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी भारत की कूटनीतिक गतिविधियां कितनी व्यापक रहने वाली हैं।

उधर, कूटनीतिक हलकों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहा है। उल्लेखनीय है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र को चार बार यानि 2014, 2019, 2020 और 2021 में संबोधित किया। 2020 में महामारी के कारण उनका संबोधन पहले से रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को देखें तो स्थिति और भी स्पष्ट है। 2024 में मोदी न्यूयॉर्क गए और भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन महासभा की सामान्य बहस में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया। 2025 में भी सामान्य बहस में भारत का प्रतिनिधित्व जयशंकर ने किया और अब 2026 में भी भारत की कमान विदेश मंत्री के हाथ में है। इस तरह तीसरे कार्यकाल में अब तक मोदी ने महासभा की सामान्य उच्चस्तरीय बहस को अब तक संबोधित नहीं किया है। इतिहासकिताबें खोजें

सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी अमेरिका इसलिए नहीं जा रहे ताकि ट्रंप से मुलाकात से बच सकें? देखा जाये तो भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव जरूर है और रूसी तेल तथा अमेरिकी शुल्क का विवाद गंभीर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जून 2026 में फ्रांस में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसलिए केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी की गैरमौजूदगी को ट्रंप से मुलाकात से बचने की रणनीति के रूप में देखा जाना गलत होगा।

बहरहाल, न्यूयॉर्क में जयशंकर का संबोधन केवल संयुक्त राष्ट्र में भारत का भाषण नहीं होगा। यह संदेश देने का अवसर होगा कि भारत दबावों के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक स्वायत्तता, ग्लोबल साउथ की आवाज और सुरक्षा परिषद में बड़ी भूमिका, इन चारों लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहता है। महासभा के मंच से भारत की कूटनीति की धार इसी संतुलन और दृढ़ता से दिखाई देगी।

क्या बलूचिस्तान में इजराइल अपनी पसंद का पेंच कस रहा है?

विकास मिश्रा

अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों के बीच अब इस बात की गंभीर चर्चा होने लगी है कि क्या बलूचिस्तान में इजराइल अपनी पसंद का पेंच कस रहा है? क्या इसे बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान की नकेल कसने की कोशिश माना जाए? यदि हां, तो इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है और इससे बलूचों को वास्तव में क्या कोई फायदा होगा? क्या यह उम्मीद की जाए कि बलूचों को कभी आजादी मिल पाएगी? ये सारे सवाल एक बार फिर से चर्चा में आ गए जब यह बात सामने आई कि गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के नेताओं को पाकिस्तान संरक्षण दे रहा है।

न केवल संरक्षण दे रहा है बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर में हमास के लिए लॉजिस्टिक भी मुहैया कराने का काम पाकिस्तानी सेना कर रही है। इजराइल ने इस संबंध में संभवतः भारत को कुछ जानकारियां भी उपलब्ध कराई थीं। इजराइल उन सभी देशों पर नजर रखता है जो उसके लिए किसी भी रूप में कभी खतरा बन सकते हैं।

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को लेकर इजराइल हमेशा ही असहज रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वह खतरनाक हो सकता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस डील हुई है, उसमें इस बात का जिक्र है कि इन तीनों में से एक भी देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा।

अब जरा सोचिए कि इजराइल यदि कभी सऊदी अरब या मिस्र पर हमला करे तो पाकिस्तान उसके खिलाफ आ सकता है। यही इजराइल की चिंता है और इसलिए इजराइल की हरसंभव कोशिश है कि पाकिस्तान किसी न किसी रूप में उलझा रहे और कंगाली की राह पर आगे बढ़ता रहे! संयोग से बलूचिस्तान के रूप मे पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल को एक महत्वपूर्ण हथियार मिल गया है।

इसी साल बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। खुद की मुद्रा बना ली है, झंडा बना लिया है। हालांकि बलूचिस्तान के लिए आजाद होना इतना आसान है नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। बलूच लड़ जरूर रहे हैं,

पाकिस्तान को उन्होंने नाकों चने चबवा दिया है लेकिन जब तक दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

हम भारतीय बलूचों का समर्थन करते हैं लेकिन भारत के लिए भी नए देश को मान्यता देना आसान नहीं है। मगर पाकिस्तान की हरकतों से नाराज सभी देश उसे सबक सिखाने और उलझाए रखने के लिए बलूचिस्तान मुद्दे को हवा जरूर देते रहेंगे। इजराइल समर्थित लोगों ने तो पंद्रह महीने पहले एक जबरदस्त शुरुआत भी कर दी थी।

इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े विश्लेषकों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट नाम से एक विशेष पहल शुरू कर दी थी, जिसे हम थिंक टैंक कह सकते हैं। यह प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले साल लॉन्च किया था।

अब जरा ध्यान दीजिए कि मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? इसका मुख्यालय भले ही वाशिंगटन में हो लेकिन थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसके संस्थापक हैं कर्नल यिगल कर्मोन, जो इजराइली सैन्य खुफिया विंग में 20 साल से ज्यादा समय तक अधिकारी थे। इतना ही नहीं वे रणनीतिक रूप से मोसाद से गहरे जुड़े हुए थे।

अब आपके मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या और वास्तव में कर क्या रहा है? अब खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोग क्या कर रहे होते हैं, यह बताना तो बहुत मुश्किल काम है लेकिन प्रोजेक्ट के घोषित उद्देश्यों पर नजर डालें तो इसका मुख्य काम उर्दू, बलोची, फारसी और पश्तो भाषाओं के पुराने दस्तावेजों और मीडिया में प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री का अंग्रेजी तथा दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके बलूचिस्तान के जमीनी मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लोगों के सामने लाना है। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही यह आरोप लगाते रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले को लेकर मोसाद का मकसद सूचना युद्ध है।

यानी बलूचिस्तान का मसला जितना ज्यादा उठेगा, उतना ही ईरान और पाकिस्तान परेशान होंगे क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका दोनों ही देशों के इलाके में शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि यह इलाका चूंकि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और पाकिस्तान तथा ईरान का इलाका है इसलिए यहां दोनों देश मिलकर कुछ परमाणु गुल खिला सकते हैं।

ईरान की हमेशा से चाहत रही है कि उसके पास परमाणु बम आ जाए! और अमेरिका ऐसा चाहता नहीं है इसलिए एक तरफ जंग चल रही है तो दूसरी तरफ इजराइल के माध्यम से दोनों की नकेल कसने की रणनीति अमेरिका अपना रहा है। यदि इस इलाके में मोसाद की पैठ हो गई तो हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी।

यही कारण है कि कुछ बलूच नेताओं को इस प्रोजेक्ट में विशेष मार्गदर्शक के रूप में रखा गया है। माना जाता है कि बलूचिस्तान में मोसाद के एजेंट काफी पहले से सक्रिय हैं। 2012 में तो यह जानकारी भी सामने आई थी कि मोसाद के कुछ एजेंट्स ने अमेरिकी अधिकारियों के रूप में बलूचिस्तानी संगठनों के नेताओं से मुलाकात भी की थी।

दरअसल इजराइल जो पेंच कस रहा है, उसमें वह अकेला नहीं है। सब कुछ महाबली अमेरिका की देखरेख में चल रहा है। बलूचिस्तान में उसका भी हित है, वहां के संसाधनों को वह भी लूटना चाहता है लेकिन उसे यह डर है कि कहीं चीन सारे संसाधन न हड़प जाए! इसलिए यह मानने में हर्ज नहीं है कि बलूचिस्तान कूटनीति का एक नया मैदान बन गया है। वहां सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। हमें भी अपने हितों का ध्यान रखना होगा!

चीन के बांध और तबाही की चिंताएं

केएस तोमर

नेपाल में 26 अगस्त को आई त्रासदी याद दिलाती है कि हिमालय अब महज एक भौगोलिक दीवार नहीं, बल्कि बेहद नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्र है। अब सवाल यह है कि जब हिमालयी आपदाएं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की प्रस्तावित पनबिजली परियोजना से टकराएंगी, तो क्या होगा? नेपाल त्रासदी के कुछ ही दिन बाद बीजिंग ने उसे आगे बढ़ाने का इरादा दोहराया है। निचले यारलुंग जांग्बो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर बनने वाली इस पांच बांधों वाली परियोजना की अनुमानित लागत 14 लाख करोड़ रुपये और इसकी क्षमता 60 गीगावाट तक हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की ओर नदी के मुड़ने से पहले 'ग्रेट बेंड' के पास इसकी प्रस्तावित जगह इसे भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय बनाती है। जलवायु वैज्ञानिकों और हिमालयी समुदायों ने चेतावनी दी है कि बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, अनियमित बारिश, अस्थिर ढलान और बिना सोचे-समझे मानवीय हस्तक्षेप पहाड़ों को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। यारलुंग त्सांगपो नदी (जो भारत में ब्रह्मपुत्र बन जाती है) पर चीन की विशाल बांध परियोजना एक नया रणनीतिक पहलू जोड़ती है। नदी के बहाव की दिशा में पड़ने वाले देशों के लिए सीधा सवाल है कि उस नदी के पानी पर किसका नियंत्रण होगा, जो लाखों लोगों के जीवन का आधार है? दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप-संवेदनशील और पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक इलाकों में से एक में इतना विशाल बांध बनाने में ऐसे जोखिम हैं, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। भूकंप, भूस्खलन या अचानक पानी छोड़े जाने से बनी प्राकृतिक आपात स्थिति सीमा-पार की आपदा में बदल सकती है। एशिया की कई बड़ी नदियों के उद्गम स्थलों पर चीन के नियंत्रण ने नदी के निचले इलाकों के देशों में चिंता पैदा कर दी है। तिब्बत के जल संसाधनों पर चीन का एकाधिकार निचले इलाकों के देशों के लिए त्रासदी और नुकसान का कारण बन सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत व बांग्लादेश में खेती, मत्स्यपालन, पारिस्थितिकी तंत्र और लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। इसका पारिस्थितिक संतुलन नाजुक है। इसके ऊपरी हिस्से में बड़े पैमाने पर दखल को क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह मामला तब और भी अहम हो जाता है, जब हिमालय के आसपास भूगोल, भू-विज्ञान और भू-राजनीति पहले से ही खतरनाक ढंग से आपस में जुड़े हुए हों। असली समस्या पारदर्शिता और गारंटी की कमी है। हाइड्रोलॉजिकल डाटा (पानी से जुड़े आंकड़े) के मामले में चीन के रवैये पर सवाल उठे हैं। 2017 में डोकलाम में हुए सैन्य गतिरोध के दौरान, चीन ने बांग्लादेश से तो डाटा साझा किया, लेकिन भारत से नहीं। इस वजह से भारत ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता, जबकि चीन समझौते के तहत भारत के साथ यह जानकारी साझा करने के लिए बाध्य है। जिस देश का नदियों के उद्गम स्थल पर नियंत्रण होता है, वह खेती, आपदा की तैयारी, ऊर्जा सुरक्षा और अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि चीन की बांध बनाने की महत्वाकांक्षाओं को भारत सिर्फ तिब्बत से जुड़ा मामला नहीं मान सकता। नेपाल की त्रासदी को एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जब पहले से अस्थिर पहाड़ी इलाकों पर खराब मौसम, भूकंप, भूस्खलन और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का दबाव एक साथ बढ़ता है, तो छोटी-सी चूक भी बड़े संकट में बदल सकती है। अब इस क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा को पूरे क्षेत्र की साझा सुरक्षा की जिम्मेदारी माना जाना चाहिए और नदी के बहाव की दिशा में पड़ने वाले देशों को मिलकर चीन से पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी इसका समर्थन करना चाहिए। पानी और भूकंप से जुड़ी जानकारी, समय पर चेतावनी और आपात स्थिति में आपसी तालमेल के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था बनाने पर जोर देना चाहिए।

फूड इंडस्ट्री में दें अपने भविष्य को उड़ान

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें न सिर्फ तरह-तरह के पकवान खाना अच्छा लगता है, बल्कि वे अच्छे स्वाद को भी भली-भांति पहचान लेते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्हें विशिष्ट प्रकार के व्यंजनों से विशिष्ट लगाव है तो आप अपने इसी लगाव को अपना भविष्य बना सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में विकल्पों की भरमार है। लीक से हटकर यह कॅरियर बेहद दिलचस्प होने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण भी है। आइए फूड इंडस्ट्री में मौजूद विकल्पों के बारे में जानें।

फूड क्रिटिक

मार्केट में कौन-से नए फूड प्रोडक्ट आए हैं, इससे लेकर किस रेस्तरां में कौन-से स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी अपनी राइटिंग स्किल के जरिए लोगों तक पहुंचाना फूड क्रिटिक का महत्वपूर्ण काम होता है। फूड क्रिटिक खाने के टेस्ट के साथ ही रेस्तरां की सर्विस के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। फूड क्रिटिक बनने के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होती लेकिन बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। बशर्ते आपमें खाने का स्वाद पहचानने, उसे बनाने का तरीका जानने और लिखने की कला होनी चाहिए।

न्यूट्रीशनिस्ट

यदि आप फूड के बारे में वैज्ञानिक तौर पर काफी कुछ जानते हैं तो आप न्यूट्रीशनिस्ट बन सकते हैं। आपको यदि ज्यादा से ज्यादा फूड के बारें में जानकारी हैं कि कौन सा फूड कैसा असर करता है। मोटे होने के लिए क्या खाएं और पतले होने के लिए क्या खाएं। डायबीटिज में क्या खाना फायदेमंद है, हार्ट अटैक से बचने के लिए किन चीजों का सेवन करें या किन चीजों का ना करें, इस तरह की जानकारियां यदि आपको अच्छी लगती हैं और आपकी इनमें गहरी रूचि है तो आप एक न्यूट्रीशनिस्ट के रूप में अपने कॅरियर को संवार सकतें है

फूड स्टाइलिस्ट

जितना खाने मे टेस्ट का होना जरूरी है, उतना ही खाने का बेहतर और क्रिएटिव दिखना भी जरूरी है। खाने को परोस कर देने का तरीका भी खाने को बेहतर बनाता है। अगर आप में यह स्किल है कि आप किसी भी तरीके के खाने को अच्छी तरह से सजाकर लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर सकतें है तो आप फूड स्टाइलिस्ट बन सकतें है। इसकी भी काफी डिमांड है क्योंकि आजकल फाइव स्टार होटल और रेस्तरां में इनकी खासी कमी है। फूड स्टाइलिस्ट बनने के लिए आपका क्रिएटिव होना काफी जरूरी है।

कलिनरी ट्रेंडोलॉजिस्ट

सिर्फ फैशन की दुनिया में ही नहीं, बल्कि फूड इंडस्ट्री में भी ट्रेंड बदलते रहते हैं। कलिनरी ट्रेंडोलॉजिस्ट समय-समय पर फूड को लेकर ग्राहकों की बदलती पसंद या नापसंद की जानकारी अपने क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। किस रेस्तरां में कौन-कौन से आइटम परोसे जा रहे हैं। किस रेस्तरां की किस खास चीज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां जुटाने का काम कलिनरी ट्रेंडोलॉजिस्ट का ही है। वे फूड इंडस्ट्री में होने वाले बदलावों को जानने के लिए फूड ब्लॉगर्स पर भी अपनी नजर बनाए रखते हैं।

प्रमुख कोर्स

- केटरिंग टेक्नोलॉजी और कलिनरी ऑर्ट्स में बैचलर डिग्री
- फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट सर्टिफिकेट कोर्स
- फूड और बेवरेज सर्विस में डिप्लोमा
- बेकरी और कनफेक्शनरी में डिप्लोमा
- किचन मैनेजमेंट में डिप्लोमा
- गेस्ट सर्विस मैनेजमेंट में डिप्लोमा
- हाउसकीपिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा
- कलिनरी आर्ट्स में एडवांस डिप्लोमा
- कलिनरी आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
- हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में एमएससी
- डाइअटेटिक्स और फूड सर्विस मैनेजमेंट में एमएससी

फूड फोटोग्राफर

जिन लोगो को खाना काफी पसंद है और वे कुछ क्रिएटिव करना चाहतें हैं तो वे इन चीजों के साथ फूड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फूड फोटोग्राफी वर्तमान में एक अच्छा कॅरियर ऑप्शन बनकर सामने आया है, जिसकी ओर युवा काफी आकर्षित भी हैं। बतौर फूड फोटोग्राफर आप किसी भी रेस्तरां या मैगजीन के लिए काम कर सकते हैं।

रेस्तरां प्रचारक

किसी रेस्तरां या होटल को फूड ब्लॉगर, मीडिया हाउसेस, मैगजीन या टीवी शो प्रोड्यूसर के माध्यम से आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी रेस्तरां प्रचारक की होती है। इनका अहम मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी रेस्तरां की तरफ आकर्षित करना है।

स्कूल साइकोलॉजी की दुनिया में तराशें रोजगार

आजकल कुछ स्कूलों में मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता की नियमित व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। मनोविज्ञान अपनी पूर्णता में एक ऐसा क्षेत्र है, जहां करियर से जुड़े अनेक विकल्प हैं। स्कूल साइकोलॉजी इसकी महत्वपूर्ण शाखाओं में एक है। स्कूलों में बढ़ते अपराधों को देखते हुए अब स्कूल साइकोलॉजिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है।

कूल साइकोलॉजिस्ट किसी भी स्कूल की टीम के मुख्य सदस्य होते हैं, जो शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान और सामुदायिक मनोविज्ञान के सिद्धांतो का पालन कर छात्रों में सीखने की क्षमता और अध्यापकों में सिखाने की क्षमता का विकास करते हैं। स्कूल मनोवैज्ञानिक बच्चों के भावनात्मक, व्यवहारिक, और शैक्षिक जरूरतों का अध्ययन कर उनकी समस्याओं का हल करने का हरसंभव प्रयास करते हैं। अगर आपकी रुचि बच्चों के मनोभाव को जानने और उनके डिप्रेशन को दूर करने की दिशा में है तो आप स्कूल साइकोलॉजिस्ट का कॅरियर चुन सकते हैं। आजकल बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र में कॅरियर की भरपूर संभावनाएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचा सकते हैं।

स्कूल साइकोलॉजिस्ट के कार्य

- स्कूल मनोवैज्ञानिक बच्चों के विकास की विशेषताओं को समझने में शिक्षक की सहायता करता है।
- प्रत्येक छात्र विकास की कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है जैसे शैशवास्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यदि शिक्षक इन विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं से परिचित होता है तो वह अपने छात्रों को भली प्रकार समझ सकता है और छात्रों को उसी प्रकार निर्देशन देकर उनको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकता है। इस बारे में पूर्ण जानकारी भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट ही टीचर को देता है।
- बच्चों के नेचर को जानने की कोशिश करता है।
- शिक्षा की प्रकृति एवं उद्देश्यों को समझने में सहायता प्रदान करता है।
- बच्चों की वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को ज्ञान देता है।

- बच्चों के अच्छे समायोजन में मदद करता है और कुसमायोजन से बचाता है।
- स्कूल मनोवैज्ञानिक कुछ खास बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी शिक्षक को देता है, जिससे शिक्षक उन बच्चों को अपनी क्लास में पहचान सकें और उनकी आवश्यकतानुसार मदद कर सकें। उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सकें और फिर उन्हें परामर्श दे सकें।
- मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चों के लक्षणों को पहचानना और ऐसा प्रयास करना कि उनकी इस स्वस्थता को बनाए रखा जा सके, यह कार्य भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट का ही होता है।

शैक्षणिक योग्यता

आप किसी भी विषय में इंटरमीडिएट पास करने के बाद साइकोलॉजी विषय में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आम तौर पर इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री दी जाती है लेकिन अगर आपने साइंस से इंटर पास किया है तो साइकोलॉजी में बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी या एमफिल किया जा सकता है।

कहां काम करते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट

- पब्लिक और प्राइवेट स्कूल
- यूनिवर्सिटीज
- स्कूल आधारित स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र
- कम्यूनिटी आधारित डे ट्रीटमेंट या आवासीय क्लीनिक और अस्पताल
- बाल न्याय केंद्र
- प्राइवेट प्रैक्टिस

पर्सनल स्किल

- बेहतर कम्युनिकेशन स्किल
- धैर्य और सहजता
- सभी उम्र के लोगों के साथ काम करने की कला
- आत्मविश्वास
- क्लाइंट को संतुष्ट करने की योग्यता
- लोगों की मदद करने का पैशन
- काम के प्रति लगाव
- संवेदनशीलता
- सहानुभूति की भावना

कहां से करें पढ़ाई

- लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमन
- जीसस एंड मैरी कॉलेज
- प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई
- क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट कॉलेज
- सोफिया कॉलेज फॉर विमन
- कमला नेहरु कॉलेज फॉर विमन
- मिठिबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स
- यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता
- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
- गार्गी कॉलेज
- जय हिंद कॉलेज
- जामिया मिलिया इस्लामिया
- ज्योति निवास कॉलेज
- विल्सन कॉलेज, मुंबई
- एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर
- यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ
- आशुतोष कॉलेज
- नेयानल डिग्री कॉलेज, जया नगर
- भीम राव अम्बेडकर कॉलेज

प्रेजेंटेशन स्किल्स से मिलेगी कामयाबी

प्रेजेंटेशन में सामने वाले को बोर नहीं, बल्कि इंप्रेस करें। तब आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे असरदार कंटेंट भी बिल्कुल बेअसर हो जाता है, जब प्रेजेंटर का स्टाइल उसके अनुरूप न हो। कई लोग प्रेजेंटेशन के दौरान नर्वस हो जाते हैं, जिसका असर उनके बोलने और बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है। यही कुछ रुकावटें हैं, जिन पर काबू पाना जरूरी होता है। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ-साथ यह कमियां दूर हो जाती हैं और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास, लचीलापन और अपने कंटेंट की गहरी जानकारी बेहद जरूरी होती है।

कटेंट पर ध्यान दें

आपके पास पहले से रोचक, संपूर्ण और सबका ध्यान खींचने वाला कंटेंट होना चाहिए। साथ ही उस मैटेरियल को सबके सामने रखने का आत्मविश्वास भी जरूरी है। अपने माहौल की समझ के साथ-साथ आपको यह ध्यान रखना भी आवश्यक होता है कि आपके संदेश का असर अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। वहीं अपने कंटेंट को तैयार करना इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस किस्म की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। फिर भी जरूरी है कि आप मुख्य बिंदुओं की पहचान कर लें। यह जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक डिटेल श्रोताओं के सामने रखी जाए।

स्टाइल पर ध्यान दें

प्रेजेंटर का स्टाइल ही एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होता है। इसलिए अपनी स्टाइल और बात करने के तरीके पर खास ध्यान दें।

पूरी जानकारी दें

बेहतर प्रेजेंटेशन दर्शकों को विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है, इसलिए जरूरी है कि विषय की आउटलाइन से शुरुआत की जाए। श्रोताओं को बताएं कि आप क्या विषय उठाना चाहते हैं, ताकि उनकी अपेक्षाएं शुरू में ही स्पष्ट हो जाएं। इससे विषय के प्रति कौतुहल भी बना रहता है।

उदाहरण से बनेगी बात

एक अन्य तथ्य यह है कि प्रेजेंटेशन की शुरुआत और अंत जोरदार तरीके से हो। यदि शुरुआत में आप श्रोताओं का ध्यान नहीं खींच पाते है तो यह आपके पक्ष में नहीं जाता। साथ ही बीच-बीच में रोचक उदाहरण देना भी जरूरी होते हैं।

सुनने वाले के बारे में जानें

आपको सुनने वालों के बारे में सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि वे कौन हैं? इसके बाद यह जानना जरूरी होता है कि प्रेजेंटेशन से वे क्या चाहते हैं? उनके लिए क्या सूचना नई होगी और क्या पुरानी? क्या उनकी कुछ विशेष जरूरतें हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए जरूरी है कि अपनी प्रेजन्टेशन की आउटलाइन आपको स्पष्ट हो। दरअसल, आपको सुनने वाले यदि संतुष्ट होते हैं तो समझिए कि आपकी प्रेजेंटेशन सफल रही।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को संगठनात्मक फेरबदल के तहत 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए। इन नियुक्तियों की घोषणा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने की और कई वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपीं। पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और आनंद को सह-प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि सतीश पूनिया जम्मू-कश्मीर और पंजाब का कामकाज देखेंगे। अनिल एंटनी को गोवा और नागालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग देशद्रोह कर रहे : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों को साफ कह रहा हूं। आप जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ये देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, जब टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे बचने वाले नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट पर लिखा कि वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है। ये हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले भाजपा आरएसएस और चुनाव आयोग ने देशद्रोह का काम किया है। इंसाफ जरूर होगा। इसके कुछ देर बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुख्य चनाव आयुक्त ने पूरी चुनाव आयोग को हाइजैक कर रखा है। उन्होंने अपने साथियों को भ्रम में रखा। आयोग का फैसला कोई अकेले नहीं ले सकता।

चुनाव आयोग का व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक

लखनऊ। केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर हुए खुलासे के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयोग की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक है। चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये बताता है कि देश के कई राज्यों की बनी सरकारें असंवैधानिक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी चुनाव ने पक्षपात किया और जिन जगहों पर सपा के वोटर थे उन्हें चिह्नित कर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हमने जब इस पर एफिडेविड के साथ शिकायत की तब भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पता चलता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। यूपी में हुए उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह बेईमानी की गई थी। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग सत्ता की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं जिससे कि सत्ता उनके पास बनी रहे।

मायावती ने भतीजे ईशान आनंद को बनाया राष्ट्रीय संयोजक

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बुधवार को बसपा की अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने का एलान हुआ। इससे पहले ईशान आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पार्टी में हालिया बदलावों के बीच ईशान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। अब उनकी जिम्मेदारी की घोषणा हो गई है। बताते चलें कि मायावती ने हाल ही में ईशान आनंद को पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देने की बात कही थी। इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म था। बुधवार को बैठक में संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। इसी दौरान ईशान आनंद को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की घोषणा कर दी गई। बताते चलें कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष शामिल हुए। इसमें मायावती ने चुनाव की जमीनी तैयारियों और प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा की।

मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में बंटी राय

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बंटा हुआ फ़ैसला सुनाया। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से ष्टछढ्ढ को हटा दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच यह तय करेगी कि क्या इस मामले की सुनवाई पांच जजों की बेंच को करनी चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस स्ट्ट शर्मा की दो जजों वाली बेंच ने प्रक्रिया से जुड़े इस खास मुद्दे पर सुनवाई की। अब मामला 2023 के संशोधन कानून से जुड़ा है, जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश (ष्टछढ्ढ) की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ शामिल किया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा हमने इन याचिकाओं और आवेदनों पर पांच दिनों से ज़्यादा समय तक सुनवाई की। संस्थागत एकजुटता के लिए एक ही राय रखना बेहतर होता। दुर्भाग्य से हमारी राय बंटी हुई है।

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष हुआ एकजुट

शरद पवार की पार्टी ने की सर्वदलीय बैठक की मांग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग में कथित मतभेदों की खबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों का हमला तेज हो गया है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने इस पूरे मामले पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह केवल किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। इसी बीच समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाम दल और दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर को लेकर सवाल उठाए हैं।

सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की खबर बेहद गंभीर है और इस पर सभी राजनीतिक दलों के साथ खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था ही कमजोर पड़ने लगे तो देश में भरोसा किस पर किया जाए। सुले ने कहा कि मामले को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह हर नागरिक के अधिकार से जुड़ा है और अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि सामने आए आरोपों में कितनी सच्चाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हट जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आरोपों की सच्चाई पर खुली चर्चा होनी चाहिए।

विवाद की शुरुआत उस रिपोर्ट से हुई, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने, फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची के प्रबंधन से जुड़े मामलों का जिक्र किया गया। विपक्षी नेताओं ने इन कथित आपत्तियों को चुनाव आयोग के भीतर गंभीर मतभेद का संकेत बताया है। हालांकि चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि एसआईआर समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने यह भी मांग रखी कि पिछले कुछ वर्षों में हुए सभी चुनावों को रद्द कर दोबारा कराया जाए। उन्होंने चुनाव आयोग की संरचना समझाते हुए कहा कि आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं और फैसले तीनों मिलकर लेते हैं। उनके मुताबिक, कोई एक व्यक्ति अकेले चुनाव आयोग नहीं चला सकता और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका बैठकों की अध्यक्षता करने की है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एसआईआर के जरिए मतदाताओं के वोट के अधिकार पर उठ रहे सवालों को गंभीर बताया।

विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई

कहा- सभी फैसले मिलकर लेते हैं

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के भीतर मतभेद और एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आयोग ने प्रेस नोट जारी कर अपना पक्ष साफ किया है। आयोग ने कहा है कि वह संविधान तहत काम करता है। आयोग के मुताबिक वह एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था है और उसके भीतर लिखित टिप्पणियां, सुझाव, तकनीकी राय और आंतरिक जांच-पड़ताल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि उसकी सभी कार्रवाइयां कानून और आयोग के निर्देशों के मुताबिक की गई हैं।

आयोग ने कहा कि इन फैसलों के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आयोग ने बताया कि उसकी कार्यप्रणाली मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित 2023 के कानून के तहत तय होती है।

आयोग के मुताबिक किसी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले सदस्यों के बीच चर्चा होती है और इस दौरान अलग-अलग राय, सुझाव या प्रशासनिक सवाल उठना सामान्य प्रक्रिया है। इनका उद्देश्य चुनावी व्यवस्था को मजबूत करना और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी संस्था में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां आना विचार-विमर्श की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग के मुताबिक अंतिम फैसला लिए जाने से पहले ये सभी टिप्पणियां निर्णय प्रक्रिया में शामिल रहती हैं। सिर्फ तीनों चुनाव आयुक्त ही नहीं, बल्कि आयोग के अधिकारी भी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। आयोग ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों की ओर से दिए गए सुझावों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और बेहतर बनाना था। इसलिए किसी आंतरिक टिप्पणी या सुझाव को सीधे संस्थागत मतभेद के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता।

आयोग ने कहा कि पिछले 10 महीनों के दौरान सामने आए कुछ चुनिंदा आंतरिक नोट्स या टिप्पणियों को ही उजागर करने से तस्वीर का केवल एक हिस्सा सामने आता है। आयोग के मुताबिक इसी अवधि में बड़ी संख्या में मंजूरियां, फैसले, निर्देश और नई पहल भी की गईं। आयोग ने बताया कि हाल के महीनों में करीब 40 नई पहल शुरू की गई हैं और कई चुनावी सुधार किए गए हैं।

यूसीसी कोई कानूनी सुधार नहीं बल्कि समाज में ध्रुवीकरण का हथियार: कांग्रेस

नईदिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कोई कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि ''विभाजन, व्यवधान और ध्यान भटकाने का एक हथियार'' तथा समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने का एक साधन है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित राज्य सरकार की समिति से बंबई उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के इस्तीफे और समिति के कामकाज को लेकर उठाए गए सवालों का हवाला देते हुए कहा कि इससे कई ''बड़े सवाल'' खड़े होते हैं। उन्होंने एक बयान में सवाल किया कि क्या संविधान सभा ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना की थी, जिसमें हर राज्य अपनी अलग समान नागरिक संहिता बनाए?

रमेश ने कहा, ''इसका जवाब है- बिल्कुल नहीं।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''क्या बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना की थी, जिसमें एक राजनीतिक दल की राजनीतिक चालों और हिसाब-किताब के मुताबिक अलग-अलग समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य एक-दूसरे से होड़ करें। इसका जवाब है- बिल्कुल नहीं।'' रमेश ने इस बात का उल्लेख किया कि 17 जून 2016 को मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को विस्तृत अध्ययन के लिए भारत के 21वें विधि आयोग के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि व्यापक अध्ययन के बाद आयोग ने 31 अगस्त 2018 को 'पारिवारिक कानून में सुधार' पर अपना परामर्श पत्र जारी किया था।

उन्होंने कहा कि परामर्श पत्र के पृष्ठ सात के अनुच्छेद 1.15 में आयोग का निष्कर्ष स्पष्ट था कि ''इस स्तर पर समान नागरिक संहिता बनाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।'' रमेश ने कहा कि इसके बजाय विधि आयोग ने भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए अलग-अलग पारिवारिक कानूनों में मौजूद भेदभाव को दूर करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उसी विधि आयोग के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया, जिसे उसने इस मुद्दे की जांच का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने अपनी-अपनी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

रमेश के मुताबिक, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हुई, जबकि गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026, असम विधानसभा ने 27 मई 2026 और मध्यप्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई 2026 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि राज्य स्तर पर बनायी जा रही ये समान नागरिक संहिता एक जैसे नहीं हैं और इनमें ''अलग-अलग प्रावधान, अलग-अलग दंड, अलग-अलग प्रक्रियाएं और कई महत्वपूर्ण छूट'' हैं। उन्होंने उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह ''कई पितृसत्तात्मक परंपराओं को अब भी जारी रखता है'' और राज्य में कानून का पालन करने वाले निवासियों के लिए भी ''कई तरह की समस्याएं'' पैदा कर रहा है।

रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ''राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बाकी दलों की आवाज दबा दी गई है'' और भाजपा उन्हें ''चुप करा रही है।'' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के लिए समान नागरिक संहिता ''कोई ऐसा कानूनी सुधार नहीं है, जिसे पूरी तरह सोच-विचार के बाद, ज्यादा से ज्यादा व्यापक विचार-विमर्श और सार्वजनिक बहस के जरिए और अधिकतम संभव सहमति के साथ लागू किया जाए।'' उन्होंने कहा, ''असल में यह विभाजन, व्यवधान और ध्यान भटकाने का एक हथियार है, लोगों को परेशान करने और डराने का एक माध्यम है, पूर्वाग्रहों को भड़काने और समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने का एक साधन है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड को 20-1 से रौंदा

काकामिगाहारा (जापान)। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए थाईलैंड के खिलाफ 20-1 की बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले 9 गोल दागे और टीम की जीत की सबसे बड़ी स्टार रहीं।

काकामिगाहारा में बुधवार को खेले गए पूल बी के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को पूरी तरह एकतरफा अंदाज में हराया। दीपिका ने दूसरे, आठवें, नौवें, 24वें, 33वें, 36वें, 39वें, 51वें और 57वें मिनट में गोल किए। उन्होंने मुकाबले में कुल 9 गोल अपने नाम किए। अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर ने भारत की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने चौथे मिनट में पहला गोल किया, जबकि इसके बाद 29वें, 35वें और 51वें मिनट में भी गोल दागे। इस तरह नवनीत ने मुकाबले में कुल चार गोल किए। रूतुजा पिसाल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल किए। उन्होंने 10वें, 11वें और 47वें मिनट में थाईलैंड की डिफेंस को भेदा। इसके अलावा अनुभवी मिडफील्डर नेहा ने 19वें मिनट में भारत के लिए एक गोल किया।

भारत की ओर से लालरेम्सियामी ने 26वें मिनट, साक्षी राणा ने 29वें मिनट और कप्तान सलीमा टेटे ने 45वें मिनट में गोल किया। भारत के आक्रामक खेल के सामने थाईलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई।

थाईलैंड की ओर से एकमात्र गोल इम्पा कुंजिरा ने किया। उन्होंने 49वें मिनट में भारत के खिलाफ गोल दागा। हालांकि, तब तक भारतीय टीम मुकाबले में बड़ी बढ़त बना चुकी थी और थाईलैंड की वापसी की कोई संभावना नहीं बची थी। इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में अपना अजेय अभियान जारी रखा। भारत ने इससे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से और थाईलैंड को 17-1 से हराया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 299 अंक चढ़ा निफ्टी 23,447 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 299.17 अंक यानी 0.40 फीसदी बढ़कर 74,828.25 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 भी 117.80 अंक यानी 0.50 फीसदी की बढ़त के साथ 23,446.80 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार के व्यापक सूचकांकों में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.69% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.88% की बढ़त के साथ बंद हुए। विनोद नायर ने कहा कि बाजार में इंट्राडे उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बनाए रखा। सितंबर का फ्लैश पीएमआई उम्मीद से बेहतर रहा, जिससे आर्थिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत मिला, जबकि महंगाई का दबाव बढ़ता नहीं दिखा। इस सकारात्मक मैक्रो माहौल ने बाजार में खरीदारी को समर्थन दिया।

फिच ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया

नई दिल्ली। फिच रेटिंग्स ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने अप्रैल- जून तिमाही में मजबूत आर्थिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती का हवाला दिया। फिच के अनुसार, शेष वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ने की संभावना है। इसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अक्टूबर की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। फिच ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है कि 2026 की पहली छमाही में व्यापार शर्तों में आई बड़ी गिरावट के बावजूद अमेरिकी-ईरान युद्ध से लगे झटके के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है।

लगातार छठे दिन सस्ता हुआ कच्चा तेल

नईदिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार छठे कारोबारी सत्र में जारी है। बुधवार, 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल डब्ल्यूटीआई 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा है। पिछले छह कारोबारी सत्रों में ब्रेंट की कीमत 9 फीसदी से ज्यादा गिर चुकी है। कच्चे तेल में यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि तेल की कीमतों में आई गिरावट को अभी संकट खत्म होने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। ब्रेंट के लिए 94 से 95 डॉलर का स्तर काफी अहम है। यह स्तर बचा रहा तो कीमतें दोबारा 102 से 103 डॉलर तक जा सकती हैं। लेकिन 94 डॉलर का स्तर टूटा तो ब्रेंट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

सर्विस सेक्टर में रफ्तार पीएमआई बढ़कर 56.5 पर

नईदिल्ली। बुधवार को जारी एचएसबीसी के फ्लैश परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सर्वे के अनुसार, सितंबर में भारत के प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस एक्टिविटी तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दोनों सेक्टर में आउटपुट में सुधार हुआ। एसएंडपी ग्लोबल द्वारा तैयार किया गया यह इंडेक्स बढ़कर 56.5 हो गया, जो अगस्त में चार साल के निचले स्तर 54.3 से सुधरा है। यह लगातार 62वें महीने 50 के उस निशान से ऊपर बना रहा जो विस्तार और गिरावट के बीच का अंतर बताता है। सर्वे में बताया गया कि सितंबर के दौरान भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में कुल नए बिजनेस में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई, क्योंकि दोनों सेक्टर में मांग में सुधार हुआ और मैन्युफैक्चरर्स ने ज्यादा सुधार दिखाया।

चीन पर चढ़ा मेड इन इंडिया का खुमार, 5 महीने में 9.36 अरब की शॉपिंग

अभिनय आकाश

जिस चीन के साथ भारत का व्यापार लंबे समय से एकतरफा नजर आता रहा है। अब भारतीय सामान की डिमांड तेजी से यहां बढ़ रही है। सिर्फ 5 महीने में चीन ने भारत से करीब 9.6 अरब डॉलर यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 39% ज्यादा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल चीन अब भारत से भी ज्यादा सामान मंगवाने लगा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों बदल रहा है? चीन के बाजार में मेड इन इंडिया की पकड़ बढ़ती कैसे दिखाई दे रही है? क्या यह भारत चीन की व्यापारिक किशस्तों में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? ताजा कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अगस्त तक 2026 के दौरान भारत का चीन को निर्यात कुल 39ब बढ़कर यहां पर 9.6 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि में भारत के पुराने ब्रिक्स सम साझेदार चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को कुल भारतीय निर्यात 34% बढ़कर यहां पर 19.9 अरब डॉलर हो गया है। यानी इन चार देशों के बीच चीन भारत के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार रहा। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना चाहता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। इस कोशिश में इलेक्ट्रॉनिक्स एक अहम सेक्टर बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल-अगस्त की अवधि में चीन को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा। इससे पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान

इलेक्ट्रॉनिक्स शिपमेंट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी।

हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स इस बढ़ोतरी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल है। भारत से चीन जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो हैं इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, स्मार्टफोनस हैं, डिस्प्ले मॉड्यूल्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर एआई डाटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मांग है इससे बढ़ रही है जिससे इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में भी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है और भारत इस बढ़ती मांग का एक हिस्सा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यही है कि चीन ने भारतीय सामान के लिए अपना पूरा बाजार खोल दिया है। या फिर यह इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि भारत चीन का व्यापार संतुलित अभी धीरे-धीरे होता नजर आएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको समझाएं तो अप्रैल और अगस्त 2026 27 के दौरान भारत ने चीन से करीब 65.49 अरब डॉलर का सामान आयत किया। यानी भारत का चीन से आयत अभी भी चीन को किए जाने वाले निर्यात से कई गुना ज्यादा है। इस 5 महीने की अवधि में चीन भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट सोर्स रहा है। इसलिए 9.6 अरब डॉलर का आंकड़ा एक सकारात्मक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जरूर है। लेकिन इसे भारत चीन के व्यापार घाटी के खत्म होने के तौर पर देखना सही नहीं होगा।

मार्च में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में चीन को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तीन गुना बढ़कर 3.18 बिलियन डॉलर हो गया, हालांकि यह बढ़ोतरी एक कम शुरुआती स्तर से हुई थी। इन शिपमेंट्स में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, स्मार्टफोन, डिस्प्ले मॉड्यूल और टेलीकॉम इक्विपमेंट शामिल थे। इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि एआई और डेटा सेंटर्स के ग्लोबल विस्तार से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स की मांग बढ़ रही है। यह बढ़ोतरी भारत के मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों के लिए अहम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उन सेक्टर्स में से एक है जिसे नई दिल्ली बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में विविधता ला रही हैं। चीन को होने वाले एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के अनुसार, अप्रैल-अगस्त की अवधि में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले लगभग 21 प्रतिशत बढ़ा।

आयुर्वेद भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ भारतीय चिकित्सा को भी दे रहे बढ़ावा : साय

2,548 लोगों ने किया रक्तदान, जिसमें 1,188 महिलाएं

ऐतिहासिक पहल गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

रायपुर। रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। रक्तदाता द्वारा दिया गया रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाकर उसके परिवार के लिए नई उम्मीद बन सकता है। आज बड़ी संख्या में माताओं-बहनों, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों का रक्तदान, देहदान और अंगदान के लिए आगे आना सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक दायित्व की प्रेरणादायी मिसाल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आयुर्वेद सेवा सम्मेलन, रक्तदान महाकुंभ एवं वृहद स्वास्थ्य जांच शिविर को संबोधित करते समय यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं दीं और रक्तदान, देहदान एवं अंगदान का संकल्प लेने वाले नागरिकों के सेवा भाव की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रदेशभर में सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनसेवा और जनकल्याण के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा का यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ रहा है। रक्तदान से लेकर जरूरतमंद बच्चों के लिए पुस्तक, खिलौने और स्टेशनरी एकत्रित करने तक अनेक गतिविधियां इस अभियान को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप दे रही हैं।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित आयुर्वेद सेवा सम्मेलन और रक्तदान महाकुंभ इसी सेवा भावना का सशक्त उदाहरण है। विशेष रूप से इतनी बड़ी संख्या में माताओं-बहनों का रक्तदान के लिए आगे आना अत्यंत प्रेरणादायी है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है और इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों का स्वेच्छा से आगे आना समाज में सेवा भावना की मजबूती को दर्शाता है।

आयुर्वेद हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य विरासत

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। भगवान धन्वंतरि और चरक-सुश्रुत जैसे महान आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व स्वस्थ जीवन और चिकित्सा की जिस समृद्ध परंपरा को विकसित किया, वह आज भी मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद, योग और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सेवा संकल्प अभियान की विभिन्न गतिविधियों तथा आयुर्वेद से जुड़े स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने आयोजकों और प्रतिभागियों से चर्चा कर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली तथा सेवा कार्यों में सक्रिय सहभागिता के लिए उनका उत्साहवर्धन किया।

स्वच्छता के लिए जनभागीदारी जरूरी मिलकर बदलें शहर की तस्वीर: धर्मजीत

स्वच्छता की शपथ लेकर छठ घाट पर उतरे जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक, दिया जनभागीदारी का संदेश

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसेवा, जनभागीदारी और सेवा भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज छठ घाट पर स्वच्छता एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने छठ घाट की साफ-सफाई की। इस दौरान महापौर ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पौधारोपण कर स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।

विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि स्वच्छ और साफ-सुथरे शहर में लोग आना पसंद करते हैं। बिलासपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा गंदगी फैलाने वालों को रोकने के लिए जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वयं जागरूक होकर स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाएं और इसे जनआंदोलन का रूप दें। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे जीवन का संकल्प बनाना होगा। जिस तरह हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी भावना से मोहल्ले, गांव और सार्वजनिक स्थानों को भी साफ रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प का उद्देश्य केवल प्रशासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है। जनभागीदारी के माध्यम से इसे जनआंदोलन का रूप देना होगा। प्रत्येक नागरिक स्वयं गंदगी नहीं फैलाने और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संकल्प ले।

कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, सीईओ जिला पंचायतसंदीप अग्रवाल,मोहित जायसवाल, पार्षदश्याम साहू, एडिशनल कमिश्नर खजांची कुमार, अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने छठ घाट की साफ-सफाई में सहभागिता निभाई तथा पौधारोपण कर स्वच्छ एवं हरित शहर के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त किया।

टॉय बैंक में खिलौनों का दान

सेवा संकल्प से बच्चों के चेहरों पर खिलेगी मुस्कान

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज रायपुर में सेवा और सामाजिक सहभागिता से जुड़े छह सेवा अभियानों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में टॉय बैंक के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित किए गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने टॉय बैंक में खिलौने दान कर अभियान की सराहना की और नागरिकों से अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की।

प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, संचालक आयुष श्री राजेंद्र कुमार कटारा एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भी टॉय बैंक में खिलौने दान कर अभियान में सहभागिता की। उनके साथ कुल 90 लोगों ने टॉय बैंक में खिलौने दान किए।

टॉय बैंक में एकत्रित खिलौनों को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के साथ उनके खेल, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को प्रोत्साहित करना है।

सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन नागरिकों को सेवा कार्यों से जोड़ने और सामाजिक सहभागिता की भावना को मजबूत करने की दिशा में पहल कर रहा है। एक खिलौना किसी बच्चे के लिए सिर्फ खेल का साधन नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली छोटी-सी खुशी भी है।

साबित हो गया ज्ञानेश कुमार भाजपा के कठपुतली - कांग्रेस

रायपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगाये गये आरोप प्रमाणित हो रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की टिप्पणियों से साफ हो गया है कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद के दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष रूप से नहीं कर रहे है। उन्होंने एसआईआर में मतदाताओं का नाम दोषपूर्ण तरीके से करवाया, उनके निर्देशन में किया गया एसआईआर दोषपूर्ण है।

महिलाओं ने रक्तदान कर तोड़ी भ्रांति

1,188 महिलाओं ने रक्तदान कर नई तस्वीर पेश की

रायपुर। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में बुधवार को जब महिलाएं रक्तदान के लिए कतार में खड़ी हुईं, तो यह दृश्य केवल एक रक्तदान शिविर का नहीं था। यह उन धारणाओं के टूटने का दृश्य था, जिनके कारण लंबे समय से महिलाओं के बीच रक्तदान को लेकर झिझक और कई तरह की भ्रांतियां बनी रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयुर्वेद सेवा सम्मेलन और सेवा महाकुंभ के रूप में आयोजित इस बड़े आयोजन में स्वास्थ्य, सेवा और जनभागीदारी एक साथ दिखाई दी।

इस शिविर में रक्तदान कर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। आयोजन में 2548 लोगों ने रक्तदान किया जिसमें 1188 महिलाओं की विशेष भागीदारी से एक नई तस्वीर सामने आई। इस विशेष रक्तदान अभियान को महिलाओं द्वारा आठ घंटे में सर्वाधिक रक्तदान के प्रयास के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण-पत्र में इस उपलब्धि को 'आठ घंटे में महिलाओं का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान' के रूप में दर्ज किया गया है।

रक्तदान के लिए पहले से ही महिलाओं और पुरुषों ने बड़े पैमाने पर पंजीयन कराया था। लेकिन इस आयोजन की असली कहानी केवल संख्या में नहीं है। इसकी असली कहानी उस सोच में बदलाव की है, जिसमें महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य को लेकर मौजूद आशंकाओं के बावजूद जांच कराई और पात्र पाए जाने पर रक्तदान के लिए आगे आईं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

स्मृति ईरानी की नियुक्ति पर आप का तंज

रायपुर। आम आदमी पार्टी के राज्य प्रभारी और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के उप-नेता मुकेश अहलावत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का राज्य प्रभारी नियुक्त करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी केडी है, लेकिन संगठन चलाने के बजाय बीजेपी टीवी सीरियल सेट करने में व्यस्त है। प्रेस को जारी एक बयान में मुकेश अहलावत ने कहा स्मृति ईरानी की ताजपोशी के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी के भाषणों में मसाले की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि टीवी डिबेट का पूरा सेट ही रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को अब ज़मीन पर कम और मैडम के रवैये को संभालने की ट्रेनिंग में ज़्यादा समय बिताना होगा। मुकेश अहलावत ने आगे कहा कि स्मृति ईरानी, जो अमेठी में हारने के बाद वहां की जनता को छोड़कर गायब हो गई थीं, उन्हें अब बीजेपी ने एक प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ भेजा है। उन्होंने याद दिलाया, एक समय था जब विपक्ष में रहते हुए स्मृति ईरानी 400 रुपये के गैस सिलेंडर को सिर पर रखकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती थीं और महंगाई के नाम पर छाती पीटती थीं। लेकिन आज, जब देश और राज्य में सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड बना इलाज का सहारा, आर्थिक संकट से बचा

बिलासपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरूरत के समय स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन रही है। बिलासपुर के सरकंडा निवासी श्री श्यामू खैरवार की पुत्री कुमारी श्रीजल खैरवार के लिए भी आयुष्मान कार्ड मुश्किल समय में उपचार का सहारा बना। अचानक आगजनी की घटना में घायल होने के बाद कुमारी श्रीजल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद उनकी स्थिति गंभीर पाए जाने पर तत्काल उपचार शुरू किया गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महंगे इलाज को लेकर परिजन चिंतित थे। इसी दौरान परिवार ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से योजना के तहत नि:शुल्क उपचार का लाभ लिया। योजना के अंतर्गत उपचार की सुविधा मिलने से परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली। इलाज के लिए उन्हें कर्ज लेने अथवा अपनी आवश्यक संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। उपचार के बाद श्रीजल स्वस्थ होकर अपने घर लौट आईं और अब सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हैं।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिल के 60 पटवारियों का बदला हल्का

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर पटवारियों की पदस्थापना में बदलाव करते हुए चार प्रमुख तहसीलों मरवाही, पेंड्रारोड, पेंड्रा और सकोला में 60 पटवारियों के हल्का नंबर बदल दिए गए है। कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा की ओर से 21 सितंबर 2026 को अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। नई पदस्थापना के बाद सभी संबंधित पटवारियों को निर्धारित समय में नए हल्के का प्रभार संभालना होगा। जारी आदेश के अनुसार मरवाही, पेंड्रारोड, पेंड्रा और सकोला तहसीलों में पदस्थ पटवारियों के हल्के बदले गए हैं। इनमें मरवाही तहसील में 22, पेंड्रारोड में 18, पेंड्रा में 10 और सकोला में 10 पटवारियों का तबादला किया गया है। इस तरह कुल 60 पटवारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन की ओर से किए गए इस फेरबदल का उद्देश्य राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में कसावट लाना बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, इनमें कई पटवारी लंबे समय से एक ही हल्के में पदस्थ थे। तबादले के बाद अब उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जारी आदेश में स्थानांतरित पटवारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित पटवारियों को तीन दिवस के भीतर अपने नए तहसील कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके बाद उन्हें आवंटित नए पटवारी हल्के का प्रभार संभालना होगा।

जनता और व्यापारी सरकार फैसला वापस ले : कांग्रेस

रायपुर। । छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यूपीआई पर शुल्क के खिलाफ आमजनता और व्यापारी दोनों है ऐसे में सरकार हठधर्मिता छोड़कर फैसला वापस ले एवं पूर्व की तरह नि:शुल्क करे। यूपीआई शुल्क के बाद व्यापारियों के द्वारा नगदी में लेनदेन किया जा रहा है।जनता के पास नगदी की कमी है।कुछ जगह यूपीआई शुल्क जनता से वसूली जा रही है। व्यापारी कह रहे है हम क्यो यूपीआई शुल्क देंगे उससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा।उनकी मांग जायज है। यूपीआई शुल्क लगने पर सरकार दावा कर रही थी कि इसे जनता से नही व्यापारी भरेंगे।जो सरासर भ्रामक है। यूपीआई को देश की डिजिटल क्रांति की पहचान बताकर प्रचारित किया गया, आज उसी के इस्तेमाल करने से जनता और व्यापारी बच रहे है, क्योंकि इससे हर वर्ग को आर्थिक नुकसान है । प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनजंय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले जनता को कैशलेस भुगतान की ओर धकेला, अब उसी व्यवस्था को कमाई का जरिया बनाने की कोशिश हो रही है। देश का छोटा दुकानदार दिनभर में दर्जनों डिजिटल भुगतान करता है। यदि हर लेनदेन पर शुल्क लगा, तो इसका सीधा असर उसके मुनाफे और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा।

रायपुर-बलौदा-सारंगढ़ फोरलेन सिर्फ कागजों तक ही सीमित: कांग्रेस

रायपुर। केंद्रीय सड़क परियोजनाओं पर केवल श्रेय की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि रायपुर- बलौदाबाजार-सारंगढ़ फोरलेन, एनएच-130 बी, छत्तीसगढ़ की उन प्रमुख सड़क परियोजनाओं में से एक है जिसका श्रेय तो भाजपा की डबल इंजन सरकार विगत ढाई वर्षों से लगातार ले रही है, लेकिन धरातल पर काम दिख नहीं रहा है। जुलाई 2024 से यह सरकार बार-बार जनता को बड़ी सौगात देने का अहसान जता रही है, लेकिन काम की रफ्तार कछुए से भी धीमी है। सवा दो साल में तो सड़क का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक यह सरकार सर्वे, डीपीआर और अधिग्रहण का काम तक पूरा नहीं कर पाई है। सरकार के खोखले वायदे और झूठे दावों से स्थानीय जनता में बेहद आक्रोश है, लंबे समय तक यह परियोजना धरातल पर आने के बजाय सिर्फ 'कागजों और क्रेडिट' तक ही सीमित रही है, जिसके चलते असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में तमाम केंद्रीय योजनाओं का लगभग यही हाल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद नया हाईवे बनाने के नाम पर वोट मांगा, स्वीकृति का भी दावा किया।

उप मुख्यमंत्री ने किया नि:शुल्क विशाल दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना ही सेवा का उद्देश्य : विजय शर्मा

रायपुर। जिन हाथों ने वर्षों से किसी का सहारा लिया, वही आज खुद गिलास उठाकर पानी पी रहे थे। जिन पैरों ने कभी साथ छोड़ दिया था, वही कृत्रिम पैर लगने के बाद बाइक चला रहे थे। कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज डोम कवर्धा में बुधवार को ये दृश्य सिर्फ एक शिविर की तस्वीर नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के जीवन में लौटती उम्मीद, बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत रही। इस बदलाव के बीच उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा दिव्यांगजनों के बीच पहुंचे और नि:शुल्क विशाल दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ करते हुए हितग्राहियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, सकल जैन समाज एवं भारतीय जैन संगटना (छत्तीसगढ़) और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित शिविर में करीब एक हजार दिव्यांगजनों का पंजीयन हुआ है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शिविर में दिव्यांगजनों से मुलाकात की और उन्हें कृत्रिम हाथ-पैर सहित विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए। शिविर में कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल सहित जरूरत के अनुसार अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपकरण प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों ने उनका उपयोग कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया। एक हितग्राही ने कृत्रिम पैर की सहायता से बाइक चलाकर दिखया, वहीं एक अन्य दिव्यांगजन ने कृत्रिम हाथ से पानी पीकर बताया कि यह सुविधा उसके दैनिक जीवन को किस तरह आसान बना सकती है।

बस्तर में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों तक भी पहुंचेगी सेवा

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह के शिविर जगदलपुर और दंतेवाड़ा में भी आयोजित किए जाएंगे। बस्तर में आईईडी विस्फोटों के कारण दिव्यांग हुए लोगों को चिन्हांकित कर कृत्रिम हाथ-पैर उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ऐसे दिव्यांगजनों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन्हें शिविर तक लाकर कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि बस्तर के अंदरूनी गांवों में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम हाथ-पैर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकें। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि शिविर का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक पहुंचे, इसके लिए सभी लोग इसकी जानकारी अपने स्तर पर साझा करें। उन्होंने समाज, संस्थाओं और आयोजन से जुड़े सभी लोगों

स्काउट-गाइड कोटा से रेलवे में चयन

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त निधि ने बढ़ाया बिलासपुर का मान

बिलासपुर। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़, जिला संघ बिलासपुर की रेंजर लीडर सुश्री निधि कश्यप का स्काउट-गाइड कोटा से दक्षिण पूर्व रेलवे में चयन हुआ है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित निधि कश्यप बचपन से ही स्काउट-गाइड गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। अपनी इस उपलब्धि के बाद उन्होंने बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल से सौजन्य मुलाकात की।

कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निधि को रेलवे में चयन पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि स्काउट-गाइड गतिविधियां युवाओं में अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं। निधि का चयन उनकी मेहनत, समर्पण और लंबे समय से स्काउट-गाइड के प्रति सक्रिय सहभागिता का परिणाम है। बचपन से स्काउट-गाइड से जुड़ी निधि ने राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया है। रेंजर लीडर के रूप में उन्होंने विभिन्न सामाजिक, सेवा एवं जनजागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.